website : - www.loktantramirror.live

लोकतंत्र मिरर

पृष्ठ : 8 RNI Reg. No. MAHHIN/2017/74134 वर्ष : 10 अंक : 51 अप्रैल 2026 मूल्य : रु. 10

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा

नई दिल्ली : लोकसभा में शुक्रवार को संविधान का १३१वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। मतदान के दौरान बिल के पक्ष में २९८ सांसदों ने वोट किया, जबकि २३० सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। २१ घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में मौजूद ५२८ सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में २९८, विपक्ष में २३० वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। विधेयक के गिरने के बाद विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है तो वहीं बीजेपी ने शनिवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

कांग्रेस, टीएमसी पर साधा निशाना

इस विरोध प्रदर्शन में एनडीए के बाकी दल भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के लिए कांग्रेस, टीएमसी पर निशाना साधा। अमित शाह ने X पर लिखा, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को ३३% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।

अमित शाह ने कहा कि अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ३३% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

मोदी-शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाने की कोशिश की : खरगे

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मोदी-शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाकर डिलिमिटेशन करने की कोशिश की और इस देश के लोकतंत्र, संविधान और संघवाद को चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया। उनकी ये चालबाजी एकजुट विपक्ष, 'इंडिया' ने भांप ली और संविधान संशोधन बिल गिर गया। हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।"

प्रियंका गाधी ने बताई विधेयक न पास होने की वजह

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया, उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा और पुरानी जनगणना से जोड़ा, जिस कारण से इसे पारित नहीं किया गया। आज, देश के विपक्ष ने अपनी दृढ़ता और एकजुटता दिखाकर भारत के लोकतंत्र और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। भारत की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक माना जायेगा।

शुक्रवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान, विधानसभाओं में २०२९ से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने के बाद, बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान कमलजीत सहरावत और कंगना रनौत सहित एनडीए सांसदों ने नारे लगाए।

महिला आरक्षण बिल गिरने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संशोधन विधेयक गिर गया। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए,असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि भारत ने देख लिया। INDIA ने रोक दिया। जय संविधान।

नारी शक्ति का अपमान : अमित शाह

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को ३३% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ३३% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहाँ नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ २०२९ लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

आशा भोसले का ९२ साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली : मशहूर गायिका आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं। रविवार १२ अप्रेल को ९२ साल की उम्र में गायिका ने आखिरी सांस ली।

आशा भोसले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। शनिवार को गायिका की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। फैंस उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे और अब उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री और फैंस को दंग कर दिया है।

सूत्रोंके मुताबिक, ब्रीच कैंडी अस्पताल की डॉ. प्रतीत समदानी ने आशा भोसले के निधन की जानकारी देते हुए कहा, "आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया।"

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, "मेरी माता जी आशा भोसले का आज निधन हो गया है। कल सुबह ११ बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आ सकते हैं। वहीं, शाम चार बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा।"

आशा भोसले के निधन की खबर से इंडस्ट्री में मातम छा गया है। फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

आशा भोसले को हुआ था चेस्ट इन्फेक्शन

बीती शाम को आशा भोसले को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनकी पोती जनाई भोसले ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि उनकी दादी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। वह सात दशक से सिनेमा पर राज कर रही थीं।

टीसीएस नासिक धर्मांतरण केस

'हिंदू लड़कियों को फंसाओ, शादी करो' गवाहों ने खोले कई चौंका देनेवाले राज

वे लोग कहते थे कि जाओ हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और उनसे शादी करो। उनका धर्म परिवर्तन कराओ, मुसलमान बनाओ।

नासिक : टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) नासिक के दफ़्तर में कथित यौन उत्पीड़न और ज़बरन धर्म परिवर्तन की चल रही जांच में एक नया दावा सामने आया है। एक गवाह ने आरोप लगाया है कि कुछ आरोपी दूसरों को जाकर हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उकसाते थे। यह बयान उन गवाहियों का हिस्सा है जिनकी जांच नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों की ओर से की गई शिकायतों की जांच कर रहे अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल उन आरोपों की जांच कर रही है जिनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ज़बरदस्ती और धार्मिक धर्मांतरण के प्रयास शामिल हैं।

नासिक कार्यालय के एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने बताया कि वे कहते थे, 'जाओ, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और उनसे शादी करो।' वे कहते थे, 'अपना धर्म बदल लो' और अपने धर्म के बारे में बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। यह 2021 से चल रहा था। TCS की HR मैडम निदा खान को भी पैसे दिए गए थे।

ये हैं धर्मांतरण के आरोपी

पिछले कुछ हफ्तों में यह मामला काफी बढ़ गया है, और इन आरोपों के संबंध में कई FIR दर्ज की गई हैं। कई कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया गया है। जिन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया गया है और जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया है, उनकी पहचान दानिश शेख, तौसीफ़ अत्तार, रज़ा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफ़ी शेख, आसिफ़ आफ़ताब अंसारी और HR मैनेजर निदा खान के रूप में हुई है।

संगठित पैटर्न कर रहा था काम

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या ऑफिस के माहौल में कोई संगठित पैटर्न या ज़बरदस्ती करने वाला नेटवर्क काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया है कि एक विशेष जांच दल (SIT) मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है, जिसमें ज़बरदस्ती और काम की जगह पर गलत व्यवहार के आरोप भी शामिल हैं। हालांकि धार्मिक धर्मांतरण के आरोप सामने आए हैं, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच अभी जारी है और नतीजे जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों पर आधारित हों

एक युवती ने बताई आपबीती

वहीं TCS में छह साल से काम कर रही एक युवती ने आपबीती बताई। उसने कहा कि उसका ट्रांसफर नासिक ऑफिस में कर दिया गया था और फिर उसे मुख्य बिल्डिंग से अलग, छत पर बने टेरेस पर अकेले काम करने के लिए कहा गया। *(शेष पृष्ठ ३ पर)*

सम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ

नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ

पाटणा : सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं. उनके साथ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद के तौर पर शपथ ली.

विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालेंगे. बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें डिप्टी सीएम पद की बधाई भी दी है. शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "नीतीश जी ने मुझ पर विश्वास जताया ये उसी का नतीजा है. उन्होंने बिहार को जिस रास्ते पर बढ़ाया है उसी रास्ते पर हमारी नई सरकार भी चलेगी." वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, "हम नीतीश कुमार जी के काम ही आगे बढ़ाएंगे." *(शेष पृष्ठ ३ पर)*

सम्राट चौधरी के साथ जनता दल (यूनाइटेड) के विजय कुमार चौधरी (बीच में) और बिजेंद्र प्रसाद यादव (दाएं) ने भी मंत्री पद की शपथ ली

विजय कुमार चौधरी : साल 2005 में जेडीयू में शामिल हुए. 2010 से वो समस्तीपुर की सरायरंजन सीट से लगातार जीतते रहे हैं. वो नीतीश मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं. उन्हें नीतीश कुमार का विश्वासपात्र सहयोगी माना जाता है.पिछली सरकार में उनके पास चार विभागों की ज़िम्मेदारी थी- जल संसाधन, संसदीय कार्य, आईपीआरडी और भवन निर्माण. उन्होंने 1982 में पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में एंट्री ली. उनके पिता कांग्रेस विधायक थे.

बिजेंद्र प्रसाद यादव : बिजेंद्र प्रसाद यादव 2005 से लगातार बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं. वो सुपौल सीट से जीतते रहे हैं. वो नीतीश सरकार के सबसे उम्रदराज़ मंत्री रहे हैं. वो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रह चुके हैं.

एमपीएससी भर्ती के नियमों में किए बड़े बदलाव

महाराष्ट्र सरकार ने 18 नई सेवाओं का किया गठन

फोटो... एमपीएससी

मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) की भर्ती प्रक्रिया के सेवा प्रवेश नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी गई है. इसमें 18 नई सेवाओं के सृजन का निर्णय भी शामिल है. सरकार के अनुसार, विभिन्न संवर्गों और सेवाओं में 574 सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन किया जाएगा. इन बदलावों में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कौशल और वरीयता मानदंड को सरल और एकरूप बनाया जाएगा तथा विभिन्न संवर्गों के बीच असंगतियों को दूर किया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि समान सेवाओं के लिए अलग-अलग अनुभव की शर्तों के कारण परीक्षाओं की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी, जिसे अब अधिक सरल, तर्कसंगत और एक समान बनाया जाएगा. सरकार ने समूह 'A' और 'B' (राजपत्रित) सेवाओं के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा के दायरे को भी बढ़ाने का फैसला किया है. वर्तमान में छह सेवाओं के तहत 57 संवर्गों में भर्ती होती है, जिसे बढ़ाकर 102 संवर्ग किया जाएगा, जिसमें 45 नए संवर्ग जोड़े जाएंगे.

इंटरव्यू के बजाय डेप्युटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे कुछ पद

संयुक्त परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विभागों के समान संवर्गों को मिलाकर 18 नई सेवाएं बनाई जाएंगी. इनमें कुल 93 संवर्ग शामिल होंगे. इन्हें 'प्रशासनिक संवर्ग समूह' और 'तकनीकी संवर्ग समूह' में विभाजित किया जाएगा, ताकि कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके. इसके अलावा, कुछ राजपत्रित पदों को नामांकन कोटे के तहत साक्षात्कार के बजाय आंतरिक पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा.

बयान में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के चलते कुछ पुराने संवर्ग अब उपयोगी नहीं रह गए हैं, जिन्हें 'डाइंग कैडर' घोषित किया जाएगा. जरूरत के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित नए पद भी बनाए जा सकते हैं. इसके साथ ही गैर-राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होगी.

'निपुण सेतु' पहल की शुरुआत

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के 'प्रतिभा सेतु' की तर्ज पर 'निपुण सेतु' पहल की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी जो साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन तक नहीं पहुंच सके उनकी जानकारी को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ साझा की जाएगी. इसे महाजॉब्स पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा.

भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग किया जाएगा. इससे उम्मीदवारों के अपने दस्तावेज जैसे अंकपत्र, ट्रांसफर प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्राप्त किए जा सकेंगे.

नितिन गडकरी ने लगाई एनएचएआई अधिकारियों को फटकार

पूछा- हाईवे सही नहीं तो टोल क्यों

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बायोकॉन कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ के सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एनएच-४४ बेंगलुरु-होसुर हाईवे की की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचएआई के संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

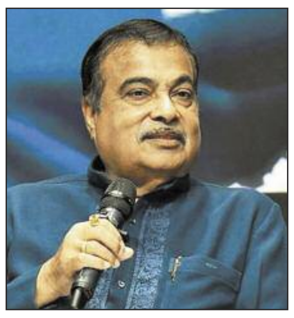

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी

सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एनएचएआई अधिकारियों को साफतौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ३० अप्रैल तक इस एनएच-४४ हाईवे की खस्ता हाल को सही दुरूस्त नहीं किया तो हाईवे बनाने वाली कंपनी समेत एनएचएआई के भी सभी संबंधित अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

जब हाईवे पर गड्ढे तो टोल क्यों

सूत्रों ने बताया कि किरण मजूमदार की शिकायत को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेहद गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को यह भी कहा कि जब हाईवे पर गड्ढे और अन्य समस्या है तो फिर टोल क्यों लिया जा रहा है? लोगों से टोल अच्छी रोड और सुविधाओं का ही तो लिया जाता है। ऐसे में अगर हाईवे पर गड्ढे होंगे और वह कहीं से धंसा होगा तो फिर टोल किस बात का। एनएच-४४ बेंगलुरु-होसुर हाईवे को आईटी कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है। जिसमें कॉरपोरेट जगत का काफी आना-जाना लगा रहता है। लेकिन पिछले काफी समय से इस हाईवे पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। कई जगह तो रोड धंस भी गई है। मूलभूत सुविधाओं में भी समस्या हो रही है।

किसने की शिकायत

ऐसे में इस हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोग खासतौर से रात के वक्त लोगों को इसका इस्तेमाल करने में बड़ी परेशानी सामने आ रही है। इन समस्याओं से कई बार एक्सीडेंट तक होने का खतरा रहता है। इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को की। जिसके बाद इस पर यह एक्शन लिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कंपनी को दी टाइमलाइन

सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी ने एनएचएआई और इस हाईवे को बनाने वाली कंपनी को साफतौर पर बोल दिया है कि ३० अप्रैल तक इस हाईवे पर जहां-जहां भी समस्या है। उसे एकदम से दुरूस्त कर दिया जाए। इस हाईवे को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। हाईवे पर लगी लाइटें और अन्य मूलभूत सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रावे गांव में वार्षिक 'आई रायबादेवी जत्रा' के दौरान एग्री-कोली समुदाय के सदस्य पवित्र बांस के खंभों 'देवकठियों' पर संतुलन बनाते हुए असाधारण कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हैं। इस जीवंत उत्सव में रंगारंग जुलूस, अनुष्ठान और २०० फीट तक ऊंचे, बारीकी से सजाए गए खंभों को उठाना शामिल है, जो हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह आस्था, परंपरा और सामुदायिक भावना का एक सशक्त प्रदर्शन है।

ईरान युद्ध खत्म होने के बाद भी वैश्विक ऊर्जा संकट लंबे समय तक क्यों बना रहेगा

नई दिल्ली : 28 फ़रवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट असल में अब शुरू ही हुआ है.न तो अस्थायी युद्धविराम और न ही ईरान युद्ध की समाप्ति वैश्विक ऊर्जा संकट और कीमतों को युद्ध से पहले की स्थिति में तुरंत ही पहुंचा सकता है.

युद्ध से पहले की स्थिति का मतलब है कि ऐसा समय जब सस्ता तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे. व्यवसाय फल-फूल रहे थे और लोगों की आमदनी चाहे जितनी भी थी, वह बढ़ ही रही थी.अब इसकी कई वजहें हैं जो युद्ध-पूर्व स्थिति को बहाल करना मुश्किल बनाते हैं.

अभी तो तेल की कमी शुरू हुयी है

फ़ारस की खाड़ी से एक टैंकर को अपने ख़रीदारों यानी आयात करने वालों तक पहुँचने में औसतन क़रीब एक से डेढ़ महीने का समय लगता है.

युद्ध ठीक डेढ़ महीने पहले शुरू हुआ था. यानी अब से दुनिया को तेल की वास्तविक कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट इस दौरान प्रभावी रूप से बंद रहा है.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल कहते हैं, "अप्रैल की स्थिति मार्च से कहीं अधिक ख़राब होगी. सबसे राहत भरे अनुमानों के मुताबिक़ भी नुक़सान दोगुना हो जाएगा. इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा."

वे कहते हैं, "स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है. ऐसे में कई देशों में जल्द ही ऊर्जा राशनिंग शुरू हो जाएगी."

युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ गईं, जबकि तेल टैंकर युद्ध से पहले लोड किया गया तेल लेकर आ रहे थे. अब जब तेल की उपलब्धता कम होगी, तो भले ही ईरान होर्मुज़ को फौरन खोल दे, कीमतें युद्ध-पूर्व स्तर पर वापस नहीं आएंगी.

तेल संकट का एक नया दौर अभी शुरू हो रहा है. आदर्श हालात में भी आपूर्ति बहाल होने में एक से डेढ़ महीने का समय लगेगा.

वास्तव में, अमेरिकी ऊर्जा विभाग की सांख्यिकी शाखा, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, यह कमी कई महीनों तक और संभवतः साल 2026 के अंत तक महसूस की जाएगी.

हालाँकि तेल का मामला थोड़ा आसान है. अगर मध्य पूर्व में स्थायी शांति बनी रहती है, तो सऊदी अरब और इस क्षेत्र के अन्य देश तेजी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं. लेकिन गैस की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है.

तेल संकट से कहीं अधिक गंभीर है गैस संकट

ईरान युद्ध से पहले दुनिया पाइपलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से एलएनजी की ओर रुख़ कर रही थी.

पाइपलाइनों को रूस ने यूरोप पर दबाव डालने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल

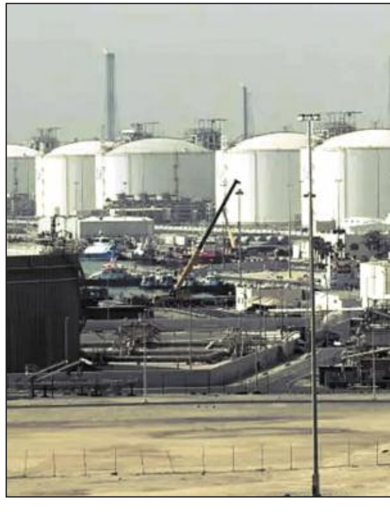

किया था, जिससे साल 2022 का वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुआ था.

कोयले की तुलना में गैस सस्ती और स्वच्छ होती जा रही थी, और ऊर्जा खपत में इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही थी. ईरान युद्ध ने दिखाया कि यह विकल्प कितना जोखिम भरा था.

युद्ध से पहले क़तर के पास दुनिया की एलएनजी आपूर्ति का 21 प्रतिशत या कुल गैस बाज़ार का क़रीब 17 प्रतिशत हिस्सा था. यह इतनी बड़ी हिस्सेदारी है जिसके लिए व्यावहारिक रूप से कोई विकल्प मौजूद नहीं है.

फातिह बिरोल कहते हैं, " युद्ध की वजह से पूरे गैस उद्योग की विश्वसनीयता को नुक़सान पहुंचा है. एलएनजी को एक भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था. लेकिन दुनिया पहले साल 2022 में रूसी गैस संकट में फंसी और अब क़तर की गैस का संकट."

एलएनजी की आपूर्ति में तेजी से सुधार संभव नहीं है. क़तर से निर्यात के लिए कोई वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं है, जबकि तेल का निर्यात कुछ हद तक ज़मीनी पाइपलाइनों से होर्मुज़ स्ट्रेट को बाईपास करके किया जा सकता है.

इसके अलावा फ़िलहाल भविष्य अनिश्चित है, जिसकी वजह से गैस की कीमतें कई महीनों तक ऊंची बनी रहेंगी.

क़तर ने नई उत्पादन क्षमता विकसित करना रोक दिया है. युद्ध के कारण उसके मौजूदा बुनियादी ढांचे के एक हिस्से पर भी असर पड़ा है.

उत्पादन को पहले जैसा करने में लंबा वक़्त

होर्मुज़ स्ट्रेट को तेल टैंकरों और गैस ले जाने वाले जहाज़ों के लिए खोलना एक मुद्दा है. जबकि डेढ़ महीने की बमबारी के दौरान क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन बहाल करना दूसरा मुद्दा है.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में स्थित 40 से अधिक तेल और गैस संयंत्रों को हमले से नुक़सान हुआ है. क़तर के रास लाफ़ान गैस फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ है. ईरानी मिसाइलों ने दुनिया के सबसे बड़े गैस लिक्विफ़ाई करने वाले संयंत्र की 17 प्रतिशत क्षमता को नष्ट कर दिया.

क़तर के अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के उपकरण ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं और इनका कोई विकल्प नहीं होता है. इसलिए इनकी मरम्मत में महीनों नहीं, बल्कि कई साल का समय लगेगा, जो तीन से पांच साल तक हो सकता है.

अन्य देशों में भी इसी तरह की समस्याएं मौजूद हैं. ईरानी ड्रोनों ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक़ में रिफाइनरियों, तेल क्षेत्रों और अन्य ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है. इनकी मरम्मत में कई महीने लगेंगे और इस पर अरबों डॉलर का ख़र्च आएगा.

युद्ध से पहले, ये धनराशि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसे मरम्मत पर ख़र्च किया जाएगा.

सरकारों के सामने संकट

युद्ध से पहले, खाड़ी देशों ने बढ़ती आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई थी.

उपभोक्ता देशों को उम्मीद थी कि तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा और गैस की आपूर्ति भी बढ़ेगी. लेकिन अब सऊदी अरब, यूएई, ईरान, क़तर और अन्य देशों को अपने संसाधनों को विकास पर नहीं, बल्कि उत्पादन के पुराने स्तरों को बहाल करने और भविष्य के हमलों के ख़िलाफ़ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर ख़र्च के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

उपभोक्ताओं को महंगी ऊर्जा के साथ-साथ परमाणु, सोलर, विंड, बैटरी और कोयले जैसे विकल्पों में किए गए निवेश और उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए भी लोगों को अधिक भुगतान करना होगा. कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए पिछले दो संकटों के विपरीत, इस बार प्रभावित देशों के पास ज़्यादा कर्ज़ लेने की क्षमता कम है.

सरकारों के सामने दोहरी समस्या है: महंगाई अधिक है, सार्वजनिक कर्ज़ और बजट घाटा भी अधिक है. धीमी आर्थिक वृद्धि से सरकारों को टैक्स से होने वाली कमाई कम होती है और आर्थिक सहायता की संभावना सीमित हो जाती है. जबकि ज़्यादा महंगाई ब्याज दरों में कटौती को रोकती है. इसके अलावा, रणनीतिक तेल भंडारों के दोहन से भविष्य के संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं.

रणनीतिक भंडार को फिर से तैयार करना अहम

तेल की कमी को दूर करने के लिए, पश्चिमी देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया. युद्ध के कारण मध्य पूर्व से रोज़ 10 से 12 करोड़ बैरल तेल बाज़ार नहीं पहुंच पाया है. रणनीतिक भंडार इसकी भरपाई के लिए रोज़ 3 से 4 करोड़ बैरल तेल जारी करते हैं.

ये उपाय 4-5 महीनों के लिए पर्याप्त हैं. लेकिन उसके बाद इस भंडार को फिर से भरना होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के कुछ भंडार बेचने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन को दोषी ठहराया. उन्होंने इसकी भरपाई करने का वादा किया, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया.

अब भंडार खतरनाक स्तर तक कम हो जाएंगे. यानी अब कानूनी और सुरक्षा कारणों से देशों को तेल की कीमतों की परवाह किए बिना धीरे-धीरे रणनीतिक तेल भंडार को फिर से भरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. रणनीतिक भंडार को फिर से तैयार करना तेल की कीमतों को बढ़ाएगा और संकट को लंबा खींच देगा.

फिर से युद्ध शुरू होने का ख़तरा

ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मध्य पूर्व की छवि वर्षों से धूमिल होती जा रही है. युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और इलाक़े में तनाव बरकरार है.

इस संघर्ष ने जोखिमों को बढ़ा दिया है, बीमा और ढुलाई की लागतों में बढ़ोतरी हुई है और यह ख़र्च लंबे समय तक या शायद स्थायी रूप से ऊर्जा की कीमतों को ऊपर बनाए रखेगा. अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि तेल की कीमतों में एक स्थायी जोखिम प्रीमियम शामिल होगा. यह समस्या केवल होर्मुज़ स्ट्रेट तक सीमित नहीं है. लाल सागर पर भी ख़तरा मंडरा रहा है. यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले और ईरान का समर्थन करने वाले समूह अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को भी निशाना बना सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि इस स्थिति पर दुनिया ने बहुत ही शांत प्रतिक्रिया दी है.

1970 के दशक के तेल संकट के कारण महंगाई, जीवन स्तर में गिरावट और राजनीतिक अशांति पैदा हुई थी. इस बार हालात और भी बदतर हो सकते हैं. फातिह बिरोल कहते हैं, "अब तक एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन यह संकट यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचेगा."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट में प्रवेश कर रहे हैं."

आसान नहीं, 'आशा' होना!

रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ९२ वर्ष की आयु में आशा भोसले का निधन हो गया। अपनी बहन लता मंगेशकर के बाद अब आशा ताई भी चली गईं और साथ ही बॉलीवुड की उस स्वर्णिम गायिकी परंपरा का अंत हो गया जो भाव, ऊर्जा और विविधता का प्रतीक थी। उनके साथ ही वह दौर समाप्त हुआ, जिसमें एक गायिका की आवाज़ फिल्म की पहचान बनती थी। लेकीन, आशा होना और बने रहना इतना आसान कतई नहीं था। आशा भोसले का जन्म ८ सितंर १९३३ को हुआ था। मात्र १० वर्ष की आयु में उन्होंने संगीत जगत में कदम रखा और अगले ८ दशकों तक उन्होंने १२,५०० से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और कई विदेशी भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ थी। रोमांटिक गीतों से लेकर डिस्को, घूमर, भजन और यहां तक कि पॉप-रॉक तक कि हर शैली में वे सहजता से ढल जाती थीं। दम मारो दम (हरे राम हरे कृष्ण), चुरा लिया है तुमने (यादों की बारात), ओम शांति ओम का टाइटल ट्रॅक, रिमझिम गिरे सावन जैसे गीतों ने पीढ़ियों को प्रभावित किया। आर.डी. बर्मन के साथ उनका जादू अलग किस्म का था। बर्मन दा ने उनकी आवाज़ में इस तरह का जज़्बा, चंचलता और आधुनिकता भरी जो पारंपरिक गायिकाओं में कम देखी जाती थी। पिया तू अब तो आजा, जानें जान, ये मेरा दिल जैसे गीत सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों को नए आयाम दिया। उमराव जान के गीतों ने रेखा को लिविंग लीजेंड बना दिया। आशा ने कभी भी सीमाओं को रेखित या स्वीकार नहीं किया। वें प्रयोगधर्मी रहीं। जब बॉलीवुड में डिस्को का दौर आया तो उन्होंने बिना हिचक आज की रात गाया। जब वर्ल्ड म्यूजिक ट्रेंड आया तो उन्होंने जॉर्ज हैरिसन और अन्य अंतरराष्टीय कलाकारों के साथ काम किया। दो बार ग्रैमी नामांकन और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार समेत अनेक सम्मान उन्हें मिले। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का अटूट प्यार था। आज की नई गायिकाओं से तुलना करें तो अंतर स्पष्ट है। आशा भोसले की आवाज़ में वह जीवन था जो सिर्फ स्वर नहीं, बल्कि अभिनय भी करता था। वें गाती नहीं थीं, बल्कि चरित्र को जीती थीं। नई गायिकाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल जैसी कई कलाकार शानदार हैं, लेकिन वे उस व्यापक कैनवास पर काम नहीं कर पा रही हैं जिस पर आशा ने काम किया। बाजार की मांग, छोटे एलबम, रिलिटी शो की संस्कृति और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने गायिकी को छोटा कर दिया है। नई पीढ़ी की गायिकाएं अक्सर ऑटो-ट्यून, हेवी बीट्स और डिजिटल प्रोडक्शन पर निर्भर रहती हैं। नई गायिकाओं में आशा जैसी भावनाएं और वह लंबी सांस की ताकत कम दिखती है जो उनकी हर धुन में झलकती थी। आज के गीत छोटे, फॉर्मूला-आधारित और सोशल मीडिया के लिए बने होते हैं। वे वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन याद नहीं रहते। जबकि आशा के गीत दशकों याद भी ताज़ा लगते हैं। इसके साथ ही संगीत का भी स्तर पहले जैसा नहीं रहा। आशा की आवाज तराशने में उनके दौर के उन महान संगीतकारों भी हाथ रहा। संगीत के उस स्वर्ण युग में संगीतकार गीत को कविता मानते थे। गायिका उस कविता को आत्मा देती थी। आज के युग में संगीत अक्सर बैकग्राउंड स्कोर बनकर रह गया है। गीत फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि ट्रेंडिंग साउंडट्रॅक बन जाते हैं। आज जब बॉलीवुड संकट से गुजर रहा है, उसके पीछे शायद संगीत की सबसे बड़ी भूमिका है।

इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज सिनेमा के पुराने गीतों को नए वर्जन में लाया जा रहा है। नए गीतों को जन्म देने के लिए पीडा सहने को कोई तयार नहीं। कहानियां कमजोर हैं और संगीत फॉर्मूला आधारित है। अभी हाल ही में आई धुरंधर में जब उनके रोल (पिया तू अब तो आ जा...) गूंजते हैं तो दर्शक झूमने लगते हैं। आशा ताई के जाने के बाद संगीत का स्वर्ण युग भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वह युग हमें याद दिलाता रहेगा कि सच्ची कला समय की सीमाओं को पार कर जाती है।...

सम्राट के सीएम बनते ही सीमांचल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर वार

अमित शाह ने दिया था ऑर्डर

किशनगंज : बिहार में सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही घुसपैठ, भ्रष्टाचार व तस्करी पर वार शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की विभिन्न जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुटी हैं।

घुसपैठियों की पहचान, भारत-नेपाल सीमा पर अतिक्रमण व सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए भी तैयारी चल रही है। इन्हीं मुद्दों पर समीक्षा के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव व डीजीपी मंगलवार को किशनगंज पहुंच रहे हैं।

इसी वर्ष फरवरी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीमांचल में थे। पहले दिन किशनगंज में सेना व प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने घुसपैठ समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। उस समय उनके साथ बिहार के गृहमंत्री व वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे।

भाजपा की अगुवाई में जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो गृहमंत्री के निर्देश को अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज हो गई। जिला प्रशासन ने भारत-नेपाल सीमा से सटे नो मेंस लैंड में अतिक्रमित जमीन को खाली करा दिया।

बॉर्डर के ध्वस्त पीलर समेत अन्य मुद्दों को लेकर सिलीगुड़ी में हाल ही में नेपाल व भारत के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमा पर बसे 22 गांवों के विकास के लिए 218 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए 112 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

होर्मुज पर विवाद चला भारत ने बड़ा दांव खेला...

गुरुवार को जीत, शनिवार को धमकी, रविवार को दुश्मन खत्म, सोमवार को मदद, मंगलवार को अकेले लड़ाई, बुधवार को शांति, गुरुवार को युद्ध... आखिर चल क्या रहा है? सत्ता में बैठे मुठ्ठीभर लोग दुनिया की शांती को तांक पर रखकर मूड ट्रेंडींग कर रहे हैं। हमआप जैसे सामान्य लोगों की यही सबसे बडी त्रसदी है। क्या दुनिया को डेटा की जगह ड्रामा चला रहा है? उधर, अमेरिका-ईरान के युद्ध में होर्मुज होने से दुनिया में तेल-गैस का संकट गहराया हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर विएतनाम, ब्रिटेन तक इसका असर देखने को मिला है। भारत में भी प्रभाव दिखा, लेकिन सरकार ने होर्मुज से पैदा टेंशन को कम करने के लिए थार प्लान एक्टिव कर दिया। होर्मुज बंद होने के तेल सप्लाई सुचारू रखने के लिए, भारत ने राजस्थान के थार रेगिस्तान की ओर रुख किया और यहां पर मौजूद ऑयल फील्ड से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया गया है।

वेस्ट एशिया में तनाव के चलते सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच सरकार कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान थार रेगिस्तान स्थित तेल क्षेत्रब से कच्चे तेल के उत्पादन में जोरदार इजाफा किया है। जोधपुर बलुआ पत्थर संरचना से अब रिकॉर्ड १,२०२ बैरल प्रति दिन कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। जबकि यहां पर क्रूड प्रोडक्शन पिछले साल ७०५ बैरल प्रति दिन था। इस हिसाब से देखें, बीते साल की तुलना में ग्लोबल तेल संकट के बीच यहां से लगभग ७० प्रतिशत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन किया जा रहा है। ऑयल इंडिया जैसलमेर के बाघेवाला तेल क्षेत्रब से कच्चे तेल को टैंकरों द्वारा गुजरात के मेहसाणा स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसी के प्लांट्स में है। वहां से इस कच्चे तेल को पाइपलाइन के जरिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित, कोयली रिफाइनरी तक भेजा जाता है। वित्त वर्ष २०२५-२६ में, ऑयल इंडिया ने अपने राजस्थान क्षेत्रब से ४३,७७३ मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, जो इससे पिछले वर्ष के ३२,७८७ मीट्रिक टन से है।

क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जबकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया हुआ है और इससे भारत समेत प्रमुख एशियाई बाजारों में तेल संकट सप्लाई बाधित होने से गहराया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रलय ने कहा कि सरकार आपूर्ति बनाए रखने लिए कदम उठा रही है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, कच्चे तेल का भंडार पर्याप्त है और देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की पूरी आपूर्ति है। हालांकि, इस त्रसदी की शुरुआत होतेही अफवाहों का बाजार भी भारत में काफी तेज चल रहा था। लेकिन, हमारे निती को सफलता मिलती गई और इंधन नियमित रूप से मिलता रहा।

दुसरी ओर, ढहरी रेगिस्तान क्षेत्रब की चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को देखते हुए तेल उत्पादन में ये इजाफा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत की जरूरतों को पूरा करने में गैर-पारंपरिक संसाधनों की क्षमता का है। ये ऑयल फील्ड १९९१ में खोजा गया था।। बीकानेर-नागौर उप-बेसिन में स्थित बाघेवाला ऑयल फील्ड, भारत के कुछ गिने-चुने तटवर्ती भारी तेल क्षेत्रें में शामिल है। ऑईल इंडिया ने १९ कुओं में सीएसएस संचालन पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ७२ प्रतिशत अधिक है।

इसके १३ नए कुएं खोदे, जिनकी संख्या अब तक ९ थीं। साल १९९१ में खोजे गए और २००.२६ वर्ग किलोमीटर में फैले इस थार तेल क्षेत्रब में ५२ कुएं हैं, जिनमें से ३३ चालू हैं। ऑयल इंडिया ने पहली बार २०१८ में सीएसएस तकनीक का प्रायोगिक परीक्षण किया, जिससे इस से बड़े पैमाने पर तेल निकालना संभव हो सका। हालांकि, यहां कच्चे तेल की चिपचिपाहट अधिक होने के कारण, कंपनी ने उत्पादन बनाए रखने के लिए डाइल्यूएंट इंजेक्शन और आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम जैसी तकनीकों को अपनाया और २०१७ से बाघेवाला क्षेत्रब से कच्चे तेल का उत्पादन जारी है। यह जोधपूर से २५० किलोमीटर की दूरी पर है।

इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के साथ ही २१० किलोमीटर लंबी पानी की पाईपलाईन, सोलार और पवन ऊर्जा प्रकल्प भी निर्माणाधीन है। यह पूरा प्रकल्प प्रोजेक्ट ग्रीन थार नाम से जाना जाएगा। स्वयंपूर्ण भारत की ओर बढता यह कदम, होर्मुझ विवाद के समय का प्रभावशाली दांव माना जाएगा।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए चुनौती

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं।

यदि इस प्रक्रिया राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चताजनक बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हसा का इतिहास नया नहीं है। १९६० और ७० के दशक नक्सल आंदोलन के दौरान हसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं।

सत्ता परिवर्तन के बाद तूणमूल एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद है। कतु यह भी एक चताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक का पालन करें।

निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
दिल्ली-९८११०५११३३

तीन नए आपराधिक कानूनों पर राष्टीय सम्मेलन

विशेष

भोपाल : गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राष्टीय न्यायिक अकादमी, भोपाल ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर 8-9 नवंबर, 2025 को भोपाल में दो दिवसीय राष्टीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभों-न्यायपालिका, अभियोजन और पुलिसपर चर्चा की गई। सम्मेलन के रिसोर्स पर्सन्स को शैक्षणिक संस्थानों और सेवारत वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चुना गया था।

केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दो दिवसीय राष्टीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण कर रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, देश ने त्वरित न्याय के एक नए युग में प्रवेश किया है। उन्होंने दोहराया कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को उपनिवेशवाद से मुक्त करना और इसे अधिक पीड़ित-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है। गृह सचिव ने राष्टीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा इन कानूनों के कार्यान्वयन में किए गए महत्वपूर्ण संस्थागत योगदान की सराहना की, जिसने नए ढांचे के तहत पेश किए गए प्रमुख तकनीकी नवाचारों के लिए मॉडल नियमों/मानक संचालन प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार किया है। इनमें ई-साक्ष्य, ई-समन, सामुदायिक सेवा और न्याय श्रुति शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी नए आपराधिक कानूनों का आधार है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही देरी की समस्या का समाधान कर एक त्वरित और अधिक कुशल न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। नए कानूनों में जाँच, मुकदमे और अन्य प्रक्रियात्मक चरणों में देरी को कम करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी एकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा कि अब हमारा ध्यान तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू किए गए सुधारों को निरंतर अपनाने, उनमें लगातार सुधार करने और उन्हें संस्थागत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। राज्य सरकारों को कार्यान्वयन की प्रगति का आंकलन करने, परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान करने और बदलती न्यायिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों, अधिसूचनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं को समय पर अपडेट करने के लिए डेडिकेटेड निगरानी तंत्र स्थापित करने चाहिए। पुलिस विभागों को जाँच और अभियोजन वर्कफ्लो के पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-साक्ष्य, ई-समन जैसी प्रणालियों का उपयोग संचालन के डिफ़ॉल्ट मोड के रूप में किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति, राष्टीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के मार्गदर्शन में, न्यायपालिका को न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में प्रयास जारी रखने चाहिए और पुलिस एवं अभियोजन मंचों के साथ न्यायालय प्रणालियों का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक, कारागार और न्यायपालिका जैसे स्तंभों के बीच नियमित फीडबैक लूप को वास्तविक समय में समस्या समाधान और डिजिटल वर्कफ्लो में सुधार के लिए संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। नए कानूनों के तहत परिकल्पित एक आधुनिक, कुशल और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपराधिक न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को पूरी तरह से साकार करने के लिए, सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से सहयोग, डेटा-आधारित निर्णय लेने और निरंतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

राष्टीय न्यायिक अकादमी के निदेशक, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि यह एक अनूठा अवसर है जहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन स्तंभ - पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका - एक साथ आए। उन्होंने संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विचार के लिए गृह मंत्रालय की सराहना की। कार्यान्वयन में जाँचकर्ताओं, अभियोजकों और न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए न्यायमूर्ति बोस ने नए तकनीकी नवाचारों, आयसीटी एप्लीकेशंस और नए फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई अवधारणाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने दोहराया कि इस तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रतिभागियों को नए कानूनी और तकनीकी परिदृश्य के बारे में सीखने, सहयोग करने और अपनी समझ को मज़बूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

द्विदिवसीय राष्टीय सम्मेलन ने एक अनूठा और अमूल्य मंच प्रदान किया जहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ- पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका- एक साथ आए। इस सम्मेलन के एजेंडे में नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू किए गए मूलभूत सुधारों, वैज्ञानिक जाँच के लिए तकनीक-केंद्रित दृष्टिकोण, न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल साक्ष्यों के संचालन, अभियोजन निदेशालय की भूमिका और समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में तैयार की गई नई समय-सीमाओं पर गहन चर्चा शामिल थी। कार्यक्रम में व्यावहारिक केस स्टडी, इंटरैक्टिव सत्र, प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञों, न्यायपालिका और पुलिस के साथ विचार-विमर्श और विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का व्यावहारिक अनुभव भी शामिल था।

उल्लेखनीय है कि 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ई-साक्ष्य, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ई-समन, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा न्याय-श्रुति और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दंड के रूप में सामुदायिक सेवा पर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत, 15,30,790 पुलिस अधिकारियों, 12,100 अभियोजन अधिकारियों, 43,941 कारागार अधिकारियों, 3,036 फोरेंसिक वैज्ञानिकों और 18,884 न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

आज तक, भारतीय न्याय संहिता के तहत लगभग 50 लाख एफआईआर दर्ज की गई हैं। 33 लाख से अधिक आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दायर की गई हैं और 22 लाख साक्ष्य आईडी बनाई गई हैं। 14 लाख से अधिक पीड़ितों को डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से ऑटोमेटेड केस अपडेट प्राप्त हुए हैं। 01 जुलाई 2024 से 38 हजार से अधिक जीरो एफआईआर दर्ज की गईं।

सम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ

(पृष्ठ १ पर से)

समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, "मैं नए सीएम के बनने से ख़ुश भी हूं और बेहद भावुक भी. मैं आज जो भी हूं वो नीतीश जी की वजह से हूं. उन्होंने ही 2014 में मुझे सीएम बनाया था. उनकी वजह से एक महादलित समाज से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना."

सम्राट चौधरी के सीएम बनने का रास्ता नीतीश कुमार के इस्तीफ़े से साफ़ हुआ.

नीतीश ने हाल ही में राज्यसभा की शपथ ली. इस तरह से बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का 21 साल का सफ़र ख़त्म हुआ.

साल 2000 में नीतीश कुमार सात दिन के लिए सीएम बने. लेकिन उनकी बतौर सीएम स्थायी पारी नवंबर 2005 में शुरू हुई.

सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं जिनकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा है. जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2 फ़ीसदी है.

वरिष्ठ पत्रकार अरविद शर्मा कहते हैं, "सम्राट बीजेपी के लिए ज़रूरी और मजबूरी दोनों बन गए थे. बीजेपी चाहती है कि लव कुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा उनके साथ आए. यानी मोटे तौर पर जेडीयू का कोर वोटर. ऐसे में किसी ऐसा नेता को आगे बढ़ाना ज़रूरी था जो इन वोटों को बीजेपी के पाले में लाने में मदद करें. चूंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम आदि बनाकर बहुत इनवेस्ट किया था इसलिए सम्राट बीजेपी के लिए ज़रूरी थे."

दरअसल, बीते कई सालों से बीजेपी राजद के कोर वोटर 'एमवाई' में से 'वाई' को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है. वाई यानी यादव जो कुल आबादी का 14 फ़ीसदी हैं.

अरविद शर्मा कहते हैं, "बीजेपी समझ चुकी है कि यादव उसे वोट नहीं करेंगे. पार्टी ने इसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को आगे लाकर ये करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुई है. ऐसे में पार्टी दूसरी जातियों पर इनवेस्ट कर रही है. चूंकि अति पिछड़ों में बीजेपी के कोई नेता सम्राट चौधरी के कद का तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए पार्टी के पास सम्राट चौधरी ही ऑप्शन के तौर पर बचते थे."

1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासन जिसका सम्राट चौधरी कभी ख़ुद भी हिस्सा रहे, उसने भी बीजेपी को ये फ़ैसला लेने के लिए प्रेरित किया.

फैजान अहमद कहते हैं कि लालू सरकार में यादव डॉमिनेंटिग थे. लेकिन नीतीश ने गैर यादव के साथ अति पिछड़ों को जोड़ा. बीजेपी इसी कास्ट कॉम्बिनेशन को अपने साथ लाना चाहती है. इसलिए सम्राट को सीएम बनाया गया.

टीसीएस नासिक धर्मांतरण केस

(पृष्ठ १ पर से)

एनडीटीवी से बातचीत में उसने कहा, मुझे छत पर अकेले काम करने के लिए कहा गया, और मेरा फ़ोन और बैग ज़ब्त कर लिया गया। जब भी मैं वॉशरूम जाने या किसी और काम से नीचे आती थी, तो सुरक्षा या किसी और बहाने से मेरा मोबाइल फ़ोन, बैग और सारा निजी सामान ज़ब्त कर लिया जाता था। हमने देखा है कि कंपनी में काम करने वाले कई युवा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था। उनका ब्रेनवॉश किया जा रहा था।

कर्मचारी ने बताया कि 20 से 25 साल की युवा महिलाओं को आसान शिकार माना जाना था। उन्हें लगता था कि इन्हें फंसाना आसान होगा। अगर आपको कोई शिकायत होती है, तो आप अपने HR के पास जाते हैं। लेकिन यहां तो HR भी इनसे मिली हुई थी। लड़की ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई, वरना आज मेरे साथ भी वही होता। यह मामला सामने आने के बाद उसका परिवार अब गहरे सदमे में है और उसकी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है।

लता दीदी ने ४५ साल पुराना गाना गाने से किया मना

आशा ने गाया तो बना सुपरहिट

लता मंगेशकर की सुरीली मखमली आवाज का जादू लोगों के दिलों तक पहुंचता था। वे बहुत ऊंचे सुरों को बिना आवाज टूटे गाती थीं। उन्होंने दिलीप कुमार के कहने पर अपने उर्दू उच्चारण पर बहुत मेहनत की थी और रोमांटिक गानों को बहुत ही कोमलता से गाती थीं।

लता जी ने हिंदी, मराठी, बंगाली सहित कई भाषाओं में ३० हजार से अधिक गाने गाए। इसमें रोमांटिक से लेकर दुखभरे गीत और भजन शामिल हैं। लता मंगेशकर अपने हर गाने को हमेशा परफेक्शन के साथ खत्म करना चाहती थीं फिर चाहें इसके लिए उन्हें कितनी ही बार रीटेक लेना पड़े।

उसूलों की पक्की थीं लता जी

लता मंगेशकर की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपनी सादगी और उसूलों के लिए जानी जाती थीं। संगीत जगत में उनके छह दशकों से अधिक के करियर में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अपनी गरिमा और सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय बड़े प्रोजेक्ट्स को मना कर दिया। लता जी ने हमेशा साफ-सुथरी गायकी को प्राथमिकता देती थीं। अगर उन्हें किसी गाने के बोल थोड़े भी भद्दे, अश्लील या 'सस्ते' लगते थे, तो वे उसे गाने से साफ इनकार कर देती थीं। उनका मानना था कि संगीत में एक तरह की पवित्रता होनी चाहिए।

कौन सा है वो शानदार गीत?

आज ऐसा ही एक किस्सा हम आपको बताने वाले हैं जब सिगर ने एक सुपरहिट गाने को मना कर दिया। हम बात कर रहे हैं साल १९६१ में आई फिल्म 'हम दोनों' के पॉपुलर गीत 'अभी ना जाओ छोड़कर' की। गाने के बोल महान कवि साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। गाने में एक लाइन है -"अधूरी आस छोड़कर, अधूरी प्यास छोड़कर..."

लता जी को लगा कि ये बोल थोड़े ज्यादा 'रोमांटिक' या 'बोल्ड' हैं और शायद उनकी छवि पर उतने सटीक न बैठें। इस वजह से लता जी ने इसे गाने से इनकार कर दिया। बाद में ये डूएट गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने रिकॉर्ड किया और ये सुपर डुपर हिट हुआ। ये गाना मूल रूप से देवा आनंद और साधना पर फिल्माया गया है।

खूबसूरती ही नहीं स्टाइल में भी अल्लू अर्जुन की पत्नी के सामने फीकी हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ४४ साल के हो गए हैं। ८ अप्रैल १९८२ को चेन्नई में जन्मे अल्लू एक्टिग के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही महत्व देते हैं। खूबसूरती और स्टाइल में उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी बड़ी-बड़ी हीरोइनों को भी मात देती हैं।

अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। दोनों एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, जहां उनके दोस्त ने उन्हें एक-दूसरे से मिलवाया। पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक-दूसरे को अपने फोन नंबर दिए और बातचीत शुरू हो गई। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और उनका रिश्ता मजबूत होता गया।

जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया और बात परिवार तक पहुंची। स्नेहा रेड्डी के घरवाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने स्नेहा के पिता को मनाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार, उनके स्वभाव और व्यवहार से प्रभावित होकर स्नेहा के पिता इस शादी के लिए राजी हो गए।

६ मार्च २०११ को अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद यह कपल दो बच्चों के माता-पिता बने।

उनके बेटे का नाम अल्लू अयान और बेटी का नाम अल्लू अरहा है। दोनों अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं।

स्नेहा की पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ

स्नेहा रेड्डी ने अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह एक पढ़ी-लिखी और सफल प्रोफेशनल महिला हैं।

स्नेहा रेड्डी, कंचरेला चंद्रशेखर रेड्डी की बेटी हैं, जो SCIENT Institute of Technology के चेयरमैन हैं। स्नेहा ने इस संस्थान में एकेडमिक और प्लेसमेंट सेल्स में डायरेक्टर के तौर पर काम किया है।

स्नेहा रेड्डी ने २०१६ में अपना खुद का वेंचर PICABOO शुरू किया। यह एक फोटो स्टूडियो है, जो प्रेग्नेंसी, न्यूबॉर्न, फैमिली और छोटे बच्चों के फोटोशूट की सेवाएं देता है।

भारत की एआय मूवी ने रचा इतिहास, दुनियाभर में 'कलियुग राइजिंग' का दबदबा

एक और जहां आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के शताब्दी वर्ष पर आधारित एआई फिल्म 'शतक' के पार्ट टू बनने की संभावनाएं तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एआई निर्मित फिल्म 'कलियुग राइजिंग' ने वैश्विक स्तर पर नौ हजार फिल्मों के बीच अपना नाम दर्ज करके इतिहास रच दिया है।

'कलियुग राइजिंग' की सफलता इस बात का संकेत है कि निर्देशक भारतीय रचनात्मकता अब एआइ तकनीक के साथ वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रही है। फिल्म निर्माता प्रतया साहा ने जागरण से बातचीत में बताया कि यह केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि तकनीकी अनुभव भी है।

उन्होंने कहा कि एआई से डरने का नहीं बल्कि उसकी मदद से कुछ असाधारण करने का वक्त आ गया है। इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि इंडस्ट्री में एआई निर्मित फिल्में बनाना मुश्किल नहीं है, केवल इसके टूल्स को सही ढंग से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। जल्द ही इस फिल्म का पार्ट टू भी रिलीज होने वाला है।

वैश्विक मंच पर पहचान बना रहीं एआई फिल्में

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब भारतीय फिल्म उद्योग भी शामिल हो गया है। हाल ही में एआई

निर्मित भारतीय फिल्म 'कलियुग राइजिंग' ने हिक्सफील्ड मेक योर एक्शन प्रतियोगिता में १०वां स्थान हासिल करके यह साबित कर दिया कि विश्व में भारतीय एआई फिल्मों का सितारा चमकने लगा है।

८६ घंटे में बनी यह फिल्म

इस फिल्म में एआई की मदद से एक साउथ एशियाई बॉक्सिग रिग तैयार किया गया है, जहां हीरो अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए लड़ने जाता है। इसके साथ ही फिल्म में चरित्र भी एआई की मदद से ही बनाए गए हैं। साहा ने कहा कि यह फिल्म बनाने में पारंपरिक प्रक्रियाओं का ही इस्तेमाल हुआ है, केवल प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में एआई का प्रयोग किया गया है। इससे फिल्म की लागत और समय दोनों में ही बचत हुई है। सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म बनाने में केवल ८६ घंटे ही लगे हैं।

क्या है फिल्मों की विशेषता

बड़े बजट की फिल्मों की लागत कम होगी। फिल्में बनाने में समय कम लगेगा। भविष्य में एआई तकनीक और कला का होगा संगम। वास्तविक अनुभव के करीब होंगी फिल्में

कैसे बनी यह फिल्म?

यह फिल्म इमैजिन इफ स्टूडियो और निर्माता-निर्देशक प्रत्या साहा के सहयोग से बनी है। स्टूडियो के संस्थापक कृष्णा और एआई कलाकार अंकुश देवा ने फिल्म के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। स्टूडियो के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत छोटे प्रयोगात्मक वीडियो से हुई थी, जिन्हें कुछ ही सप्ताह में छह करोड़ से अधिक व्यूज मिले। इसी सफलता ने एआई आधारित फिल्म निर्माण को नई दिशा दी। निर्माताओं का कहना है कि एआई और लाइव-एक्शन के संयोजन से फिल्म निर्माण का भविष्य तैयार हो रहा है।

होस्टिंग पर ट्रोल हुई आलिया के सपोर्ट में सोना महापात्रा

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल में एक अवॉर्ड शो में होस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं. लोगों का कहना है कि उनकी कॉमेडी फीकी थी और वे प्रियंका चोपड़ा की नकल कर रही थीं. इस बीच, बेबाक सिंगर सोना महापात्रा आलिया के बचाव में उतर आई हैं. सोना ने बॉलीवुड अवॉर्ड शोज की कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा कि लाइव स्टेज पर खड़े होकर लोगों को हंसाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. उन्होंने आलिया भट्ट को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि स्टेज पर जब कोई परफॉर्म करता है, तो वहां 'रीटेक' का मौका नहीं मिलता. बॉलीवुड में लाइव शो करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टंट है और आलिया ने जो किया, उसके लिए हिम्मत चाहिए.

सोना महापात्रा ने सिर्फ ट्रोलर्स पर ही नहीं, बल्कि अवॉर्ड शो में बैठे बॉलीवुड के बड़े सितारों पर भी जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब आलिया स्टेज पर मेहनत कर रही थीं, तब सामने बैठे सितारों के चेहरे पर न तो कोई रोमांच था और न ही उन्होंने आलिया का हौसला बढ़ाया. सोना के मुताबिक, बॉलीवुड में लोग जितने ज्यादा 'सफल' होते जाते हैं, उतने ही कम उदार और सपोर्टिव होते जाते हैं. वहां तालियों की जगह लोग मन ही मन हिसाब-किताब लगाने लगते हैं और सपोर्ट करने के बजाय एक-दूसरे से खामोश मुकाबला करते हैं. सोना ने शबाना आजमी के फैशन शो का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी रैंप पर लोग पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन सामने बैठे स्टार्स की एनर्जी जीरो होती है.

बॉलीवुड की 'झूठी यूनिटी' पर उठाए सवाल

सिगर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखकर आलिया का सपोर्ट किया और बॉलीवुड की 'झूठी यूनिटी' पर सवाल उठाए. उन्होंने साफ कहा कि किसी को ट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन उस जगह खड़े होकर देखना बहुत मुश्किल. सोना की इस बात से कई यूजर्स सहमत नजर आ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के इस रवैये पर चर्चा शुरू हो गई है. यह पहली बार नहीं है जब आलिया भट्ट को निशाना बनाया गया हो, इससे पहले भी उनके निजी रिश्तों और अभिनय को लेकर उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा है. लेकिन इस बार सोना महापात्रा ने इंडस्ट्री के अंदरूनी माहौल और सितारों के ठंडे बर्ताव को एक्सपोज करके एक नई बहस छेड़ दी है.

'है जवानी तो इश्क होना है' का पहला लुक हुआ रिलीज

रोमांटिक अंदाज में मृणाल को बाहों में भरते दिखे वरुण धवन

वरुण धवन और मृणाल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली रोमांटिक कॉमेडी 'है जवानी तो इश्क होना है' से अपना पहला लुक शेयर किया है. इसमें वरुण मृणाल को पीछे से गले लगाते हुए नजर आए, जिससे उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री का अंदाज साफ दिख रहा है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "लेकिन जवानी में इश्क बार-बार होता है", जिससे फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई.

पोस्टर सामने आते ही फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आखिरकार, है जवानी तो इश्क होना है." वहीं दूसरे ने कहा, "दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त लग रही है." जबकि, कई ने "इंतजार नहीं होता" और रेड हार्ट जैसी कमेंट से प्यार बरसाया. इससे साफ है कि दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है.

इससे पहले फिल्म का एक और सीन पहले ही सामने आया था, जिसमें वरुण और पूजा हेगड़े नदी के किनारे रोमांटिक पोज में दिखाई दे रहे हैं.

फिल्म की कहानी और कास्ट

फिल्म डेविड धवन के निर्देशन में बन रही है. इसमें वरुण और मृणाल के अलावा पूजा हेगड़े, मौनी रॉय, चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और अली असगर भी नजर आएंगे. यह वरुण और उनके पिता डेविड धवन की चौथी फिल्म है, पहले की तीन सफल फिल्में 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा २' और 'कुली नं. १' हैं.

फिल्म का नाम के पॉपुलर गाने "इश्क सोना है" से लिया गया है, जो सलमान खान और सुष्मिता सेन की फिल्म 'बीवी नंबर १' में था.'है जवानी तो इश्क होना है' १२ जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

समय रैना ने अमिताभ बच्चन को किया रोस्ट!

समय रैना ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान केबीसी का किस्सा शेयर किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को रोस्ट भी किया। उन्होंने बताया कि केबीसी के बाद उनकी इमेज क्लीन हो गई थी, लेकिन वह शो में रियल नहीं थे।

समय रैना ने कहा कि उनके मन में ख्याल आ रहा था कि वह अमिताभ बच्चन से पूछे, "सर, आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पर क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप। यह नहीं किया ना मैंने वहां पर। मैंने यह कि मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। समय रैना ने बताया कि उन्होंने शो में झूठ बोला था कि उनकी दादी अमिताभ बच्चन की फैन हैं, क्योंकि उनकी दादी के निधन को ७ साल हो गए हैं। समय ने कहा कि आप इंडियन इंटरनेट पर ईमानदार नहीं हो सकते हो। आप वैसे नहीं रह सकते, जैसे हो। आप खेल खेलते हैं, आप माहौल के हिसाब से चलते हैं।

समय रैना ने बताया कि कंट्रोवर्सी के बाद तन्मय ने उन्हें कॉल किया और उनसे कहा कि किसी पावरफुल सोर्स से मदद लें। स्टैंड-अप कॉमेडियन ने कहा कि उन्हें अपने कॉन्टैक्ट में एक ही बड़ा सोर्स मिला, वो केबीसी हेड थे। उन्होंने कहा, "मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है, मेरे फोन में सबसे पावरफुल कॉन्टैक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। जब मैं केबीसी में गया था तो उन्हें मैं बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने नंबर दिया था और कहा था कि कभी कुछ होगा तो बताना।" समय ने आगे कहा, "मैं इतना डेस्पेरेट था कि मैंने उन्हें पहला ही मैसेज यह कर दिया कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं समय रैना हूं। याद है कि मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना। वो कह रहे, क्या हुआ। मैंने कहा, क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सिंगापुर में हूं, क्या हुआ। मैंने कहा, मेरे शो में बीयरबाइसेप आया और उसने एक जोक मार दिया सर और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं।

पलाश-स्मृति का हुआ पैचअप... क्या अब होगी शादी?

साल २०२५ में ऐसी कई घटनाएं हुईं जिन्होंने हर किसी का ध्यान खींचा और इन्हीं में से एक थी भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल। पलाश और स्मृति की शादी होने वाली थी लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों का रिश्ता टूट गया।

हल्दी-मेहंदी के बाद दोनों की शादी टूट गई, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बाद सबके मन में सवाल है कि क्या दोनों फिर से शादी करने जा रहे हैं? आइए जानते हैं...

पलाश-स्मृति का हुआ पैचअप?

पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शादी जब टूटी तो हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हुई। पलाश पर चीटिग के आरोप लगे। ठीक एक दिन पहले ही दोनों की शादी (Smriti Palash Wedding) टूट गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों का पेंचअप हो गया है। अब ये सवाल कहां से आया, ये भी जान लीजिए।

दरअसल हाल ही में पलाश-स्मृति के परिवारवालों ने एक दूसरे से मुलाकात की है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पलाश मुच्छल की बहन और सिगर पलक मुच्छल नजर आ रही हैं। पलक के साथ इस वीडियो में स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना भी नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा यहां पलक के पति मिथुन भी साथ दिखे। इन तीनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के

बाहर स्पॉट किया गया। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, अब एक साथ इन तीनों का दिखना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है।

क्या शादी करेंगे पलाश-स्मृति?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि, तीनों एक साथ खड़े होकर पोज दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा पलक (Palak Muchhal) ने यहां स्मृति के पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। ये नजारा कैमरे में भी कैद हुआ है। अब इनके एक साथ दिखने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या परिवार पलक-स्मृति के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।

क्या वाकई में दोनों शादी करने जा रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं और सभी के मन में यह आ भी रहा है। माना जा रहा है कि पलाश और स्मृति के परिवार के बीच के रिश्ते भी अब सुधर रहे हैं।

आपको बता दें कि जब पलाश और स्मृति की शादी अचानक से मंडप में जाने से ठीक पहले टूटी तो हर किसी के मन में सवाल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। उस वक्त खबरें आईं कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हुई है, जिसके चलते शादी टली है। हालांकि काफी वक्त बाद कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए और पलाश पर चीटिग के आरोप लगे थे।

हालांकि अब इतने महीनों बाद एक बार फिर से ये सुगबुगाहट है कि क्या वाकई में दोनों परिवारों के रिश्ते सुधरे हैं और क्या वाकई में स्मृति-पलाश दोबारा शादी करने पर विचार कर रहे हैं।

खास खबरें

महाराष्ट्र के १५ जिलों में लू का हाई अलर्ट

कामगारों के लिए जारी हुई विशेष मानक कार्यप्रणाली

मुंबई : महाराष्ट्र में बढ़ते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनज़र राज्य सरकार ने राज्य हीट एक्शन प्लान घोषित किया है. इसके तहत असंगठित कामगारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक मानक कार्यप्रणाली जारी की है.

इन नियमों के अनुसार, मौसम विभाग के अलर्ट के आधार पर दोपहर 12 से 4 बजे तक कामगारों को अनिवार्य विश्राम देना होगा. साथ ही काम के समय को सुबह 6 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे के बीच रखने की सिफारिश की गई है.देश के सबसे अधिक गर्मी-संवेदनशील राज्यों में महाराष्ट्र का समावेश होने के कारण यह निर्णय लिया गया है. हीट स्ट्रोक और आपदाओं के मामलों में भी महाराष्ट्र देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है.

इस संबंध में आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीष महाजन ने कहा कि, "देश के दस प्रमुख गर्म राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल है. जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में तापमान 47 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं."

राज्य हीट एक्शन प्लान के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश क्षेत्र के 15 जिलों को अत्यधिक गर्मी के लिए उच्च जोखिम वाला माना गया है. इनमें शामिल हैं:लातूर, अमरावती, यवतमाल, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, जळगांव, नंदुरबार, धुले और नांदेड़.यह सलाह मुख्य रूप से इन उच्च जोखिम वाले जिलों के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर आंतरिक और अर्ध-शुष्क इलाकों में लागू होगी.

मानक कार्यप्रणाली किन पर लागू होगी

यह मानक कार्यप्रणाली महाराष्ट्र के सभी उच्च तापमान-जोखिम वाले शहरी क्षेत्रों में कार्यरत महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों पर लागू होगी.विशेष रूप से बाहरी असंगठित कामगारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें शामिल हैं : सड़क विक्रेता, निर्माण मजदूर और दैनिक वेतनभोगी, ट्रैफिक पुलिस, सफाई कर्मचारी, गिग और डिलीवरी वर्कर, रिक्शा चालक और हमाल.

इसके अलावा कोयला खदान मजदूर, घर-आधारित कामगार, कचरा बीनने वाले, सुरक्षा गार्ड, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, फैक्ट्री वर्कर, परिवहन और खाद्य क्षेत्र के कामगार, किसान और पशुपालक भी इसमें शामिल हैं.

सरकार की सख्ती पर छलका मुंबई के टैक्सी-ऑटो चालकों का दर्द

मुंबई : महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा का विवाद बड़ा हो सकता है। क्योंकि राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 1 मई से टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए मराठी अनिवार्या करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसको लेकर यूनियन विरोध कर रहा है, तो वहीं ऑटो और टैक्सी चलाने वाले एक ड्राइवर का कहना है कि यह सब काली पीली को बंद करने की यह चाल है, सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चाहती है कि मुंबई से सिर्फ प्राइवेट गाड़ी चले। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें मराठी समझती है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन मतलब यह नहीं की हमें मराठी पसंद नहीं, या हम सीखना नहीं चाहते है। बता दें कि मुंबई समेत एमएमआर में अधिकांश ऑटो और टैक्सी चलाने वाले जो ड्राइवर है, वे नॉन मराठी स्पीकर है, यह ड्राइवर मूल उत्तर भारत, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के है। यही वजह है कि उन्हें मराठी बोलने में समस्या होती है।

मुंबई टैक्सीमैन यूनियन के सेक्रेटरी ए. एल. क्वाड्रोस का कहना है कि मराठी अनिवार्य करनी थी, तो पहले दिन से करते। अब करके कोई फायदा नहीं हो। हम इस फैसले का खंडन करते हैं। मुंबई ऑटो रिक्शा-टैक्सी मेन्स यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव का कहना है कि हम इस निर्णय का निषेध करते है। ड्राइवर का घर ऑटो और टैक्सी से चलता है। यदि वो एग्जाम में फेल हो जाते है, तो उनका लाइसेंस रद्द होगा, उनका घर चलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

मुंबई में ऑटो ड्राइवर सुलेमान खान ने कहा कि हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन इसे जबरन थोपना ठीक नहीं है। भाषा विवाद से 2 लोगों के बीच घृणा पैदा करेगा। ड्राइवरों के लिए मराठी में परीक्षा की अनिवार्यता उचित नहीं है। वर्षों से ड्राइविंग कर अपना घर संभाल रहे है। भाषा नहीं आने पर क्या इस काम को भी छोड़ दें? टैक्सी ड्राइवर उजैर खान ने कहा कि यह तो गलत है। भारत में एकजुटता है. इसे भाषा के नाम पर बांटना ठीक नहीं है। अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति केंद्र सरकार के लिए काम करता है, तो वह किसी भी राज्य में नौकरी करेगा, लेकिन क्या वह हर राज्य की भाषा सीखेगा? मराठी भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अचानक से सरकार द्वारा लोगों पर थोप देना, बिल्कुल उचित नहीं है।

टीसीएस नासिक में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस में खुलासे पर खुलासे

अंडरकवर महिला पुलिस, मलेशिया लिंक

नासिक : महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) के BPO कैंपस के अंदर संदिग्ध गतिविधियों के बारे पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। यह सूचना पुलिस को इस साल फरवरी में मिली। पुलिस ने इस पर एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में महिला पुलिसकर्मियों को टीसीएस के उस दफ्तर में हाउसकीपिंग स्टाफ़ के तौर पर तैनात किया गया। इस कार्रवाई के ज़रिए एक कथित धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफ़ाश हुआ। इस केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब कार्पोरेट जिहाद जैसे चर्चाएं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है। इसी बीच इस रैकेट के अंतरराष्ट्रीय तार जुड़ने की भी आशंका है। पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है।

जांचकर्ताओं का कहना है कि जांच के दौरान एक व्हॉट्सअॅप चैट मिली। इसमें मलेशिया से जुड़े कुछ संदिग्ध शामिल हैं। एक स्पीकर और पीड़ितों के बयानों से भी इस केस के अंतरराष्ट्रीय लिंक के तार मिले हैं। सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि टीसीएस दफ़्तर के भीतर से ही एक कहीं ज़्यादा बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है।

अब तक 9 एफआईआर, 12 केस सामने आए

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सूत्रों ने बताया कि अब तक कम से कम 12 कर्मचारियों की पहचान कथित टारगेट के तौर पर की गई है, जो पहले नौ थी। अब तक नौ FIR दर्ज की गई हैं, जिन्हें आठ महिलाओं और एक पुरुष ने दर्ज कराया है। इन FIR में यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर रेप, धार्मिक हेरफेर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

18 से 25 साल की लड़कियां टारगेट

एफआयआर के मुताबिक, आरोपी कर्मचारियों ने कथित तौर पर अपनी महिला सहकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की और उन पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। 18 से 25 साल की उम्र की महिलाओं द्वारा रिपोर्ट की गई ये घटनाएं, कथित तौर पर दो से तीन साल की अवधि में हुईं, जिनकी शुरुआत लगभग 2022 में हुई थी। 9 कर्मचारियों के अलावा, तीन और लोग भी इस रैकेट से प्रभावित हुए हैं और उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। हालाकि, सामाजिक बदनामी और निजी चिताओं का हवाला देते हुए, उन्होंने अभी तक औपचारिक शिकायतें दर्ज नहीं की हैं।

पुलिस ने बताया कि अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कई टीम लीडर और इंजीनियर हैं। वहीं अन्य के खिलाफ जांच जारी है। TCS HR मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है। जांचकर्ता उसकी भर्ती प्रक्रियाओं और संगठन के भीतर उसकी भूमिका की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

विदेश में नौकरी और लग्जरी लाइफ का लालच

एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने टीसीएस परिसर के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ़ के भेष में चार महिला कांस्टेबलों को तैनात किया। उनकी जानकारी, लोगों के आपसी मेलजोल का पता लगाने और पीड़ितों के लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने में बहुत अहम साबित हुई है। इमरान नाम का एक व्यक्ति, जिसका कथित तौर पर मलेशिया से संबंध है, व्हॉट्सअॅप बातचीत में सामने आया है। जांचकर्ताओं को शक है कि वह कोई उपदेशक हो सकता है, जिसे वीडियो कॉल के ज़रिए कर्मचारियों से मिलवाया गया था; इन कॉल्स में उसने महिलाओं को ज़्यादा वेतन वाली नौकरियों और बेहतर जीवनशैली के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। उसकी पहचान और भूमिका की अभी भी पुष्टि की जा रही है।

टारगेट पर वॉट्सऐप ग्रुप पर चर्चा

एसआईटी ने ऐसे व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स का पता लगाया है जिनमें आरोपी शामिल थे। इन ग्रुप्स में कथित तौर पर सहकर्मियों के बारे में चर्चा की जाती थी, संभावित लक्ष्यों की पहचान की जाती थी और रणनीतियों को आपस में तय किया जाता था। अब फ़ॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके डिलीट की गई चैट्स को वापस हासिल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये चैट्स, आरोपियों के इरादों और इस पूरे ऑपरेशन के दायरे को समझने में बहुत अहम साबित हो सकती हैं।

जांचकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए बयानों से एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है। आरोपियों में छह टीम लीडर्स और HR एग्जीक्यूटिव निदा खान ने कथित तौर पर अपने सहकर्मियों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया। उनके साथ गलत तरीके से पेश आए और उन पर इस्लामिक रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए लगातार दबाव डाला। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाते हुए उन पर टिप्पणियां की गईं।

एचआर मैनेजर निदा खान फरार

एचआर मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है, जबकि जांचकर्ता कंपनी के अंदर उसके भर्ती पैटर्न और भूमिका की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने टीसीएस से आंतरिक जांच-पड़ताल और भर्ती से जुड़े फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने आरोप लगाया कि कंपनी के चार-पांच मुस्लिम कर्मचारियों और कुछ अधिकारियों ने लड़कियों को नौकरी और आकर्षक वेतन का लालच देकर फंसाया। दावा किया कि उन पर नमाज़ पढ़ने और रोज़ा रखने का भी दबाव डाला गया।

सूत्रों के अनुसार, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि यह नेटवर्क, जितना शुरू में सोचा गया था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसके जवाब में, टीसीएस ने कहा कि वह 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की सख्त नीति का पालन करता है, और इस बात की पुष्टि की कि जिन कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जांच चल रही है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

कब खुलेगा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक?

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और पुणे के लोगों अगले महीने बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पहले यह अपडेट सामने आया था कि कई साल से निर्माणधीन मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट 1 मई को शुरू हो जाएगा, लेकिन अब यह संभावना जताई जा रही कि इसके खुलने में कुछ और देरी हो सकती है, हालांकि इसके मई में खुलने की पूरी संभावना है। इसके बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर बेहद सुहावना और रोमांचकारी हो जाएगा। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। ताजा वर्क अपडेट के अनुसार अब सिर्फ़ फाइनल बिटुमेन लेयर और सतह पर लेन मार्किंग बाकी है। लोड टेस्टिग भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द इसकी सौगात दे सकते हैं।

60 मंजिल ऊंचे ब्रिज से गुजरेंगे वाहन

मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में दो 8-लेन वाली जुड़वां सुरंगें हैं। मुख्य सुरंग की चौड़ाई लगभग 23.5 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे चौड़ी रोड सुरंगों में से एक है। टाइगर वैली के ऊपर बना 650 मीटर लंबा केबल-स्टेड ब्रिज इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण है। इसके हीराकार खंभे 182 मीटर ऊंचे हैं। यह ऊंचाई 60 मंजिला इमारत के बराबर हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा केबल-स्टेड ब्रिज है। यह नया लिंक खंडाला घाट के तीखे मोड़ों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को बाईपास करता है, जिससे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर सुरक्षित हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा क्रियान्वित इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत लगभग 6,600 करोड़ रुपये के करीब है है।

लोणार झील का पानी बदल रहा रहस्यमयी ढंग से अपना रंग

पुणे : प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी भी है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार क्रेटर देश की धरती पर एक अनोखा प्राकृतिक चमत्कार है। यह क्रेटर लगभग 35 हजार से 50 हजार साल पहले किसी उल्कापिड के टकराने से बना था। शुरू में इसे ज्वालामुखी क्रेटर समझा गया था लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह उल्कापिंड की टक्कर से बना है।

यह दुनिया में बेसाल्ट चट्टानों पर बना एकमात्र इम्पैक्ट क्रेटर है, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के क्रेटरों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोनार क्रेटर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार गांव के पास स्थित है। यह दक्कन पठार के अंदर है, जहां 65 मिलियन साल पहले हुए विशाल ज्वालामुखीय विस्फोटों से बनी बेसाल्ट चट्टानें फैली हुई हैं। 1823 में ब्रिटिश अधिकारी सी.जे.ई. अलेक्जेंडर ने इसे पहचाना था। इसके बाद लंबे समय तक भ्रम बना रहा कि यह ज्वालामुखी क्रेटर है। 1970 के दशक में 'मास्केलिनाइट' नामक प्राकृतिक कांच की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि यह उल्कापिंड की तेज टक्कर से बना है।

महाराष्ट्र का मशहूर पर्यटन स्थल

लोनार क्रेटर न सिर्फ भूविज्ञान का रहस्य है बल्कि पर्यटन स्थल भी है। यहां घूमने वाले पर्यटक इस अनोखी झील और क्रेटर की सुंदरता का आनंद लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोनार ब्रह्मांड की टक्करों और पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है, जिसे लेकर तमाम स्पेस एजेंसी काम भी कर रही हैं।

क्रेटर के अंदर एक झील बनी

मास्केलिनाइट केवल तेज गति की टक्करों में ही बनता है। क्रेटर का व्यास औसतन लगभग 1,830 मीटर यानी लगभग 1.8 किलोमीटर है और यह करीब 150 मीटर गहरा है। इसका किनारा आसपास की जमीन से लगभग 20 मीटर ऊंचा उठा हुआ है। क्रेटर के अंदर एक झील बनी हुई है, जो नमकीन और क्षारीय है।अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उपग्रह ने साल 2004 में इसकी तस्वीर ली थी, जिसमें झील हरी-नीली दिखाई देती है और चारों ओर वनस्पति, खेत और बस्तियां साफ नजर आती हैं। ।

मौसम के अनुसार बदलता रहता है रंग

वैज्ञानिकों ने सैंपल लिए और पाया कि यह हेलोआर्किया जैसे नमकीन पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ। गर्म और सूखे मौसम में पानी का स्तर कम होने से खारापन बढ़ गया, जिससे ये जीव बढ़ जाते हैं और गुलाबी रंग पैदा करने लगते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर या ईरान की लेक उर्मिया में भी ऐसा होता है। हालांकि, लोनार झील का रंग हमेशा नहीं रहता बल्कि यह मौसम के अनुसार बदलता रहता है।

भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों ने यहां काफी अध्ययन किया

यह क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए खास है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों पर बना है जो चंद्रमा की सतह से मिलता-जुलता है। नासा के साथ ही भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों ने यहां काफी अध्ययन किया है। हाल के वर्षों में झील का पानी बढ़ने की समस्या भी सामने आई है, जिससे पास में स्थित प्राचीन मंदिर प्रभावित हुए हैं और झील का रासायनिक संतुलन प्रभावित हो रहा है

फर्जी दस्तावेज से बनी पार्षद; सहर शेख की बढी मुश्किलें

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा से एआईएमआईएम और 'कैसा हराया' फेम पार्षद सहर शेख की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. ठाणे के तहसीलदार ने सहर शेख और उनके पिता यूनुस शेख के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करके सरकार को गुमराह करने के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है.

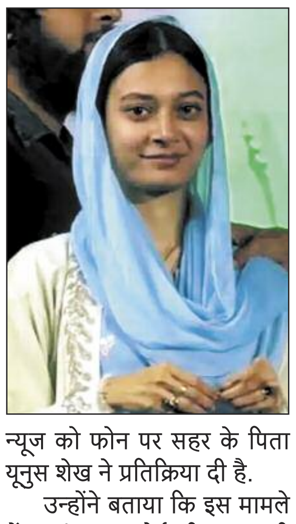

इस मामले में सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी. MIM की कॉर्पोरेटर सहर शेख पर सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगा है. यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र में एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था.

फर्जी जाति प्रमाण किया प्राप्त

सहर शेख ने यह जाति प्रमाण पत्र मुंबई शहर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया था. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सहर शेख की कॉर्पोरेटर की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है. इस बीच एबीपी न्यूज को फोन पर सहर के पिता यूनुस शेख ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है. हमें अदालत से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है. मैं आज मुंब्रा में नहीं हूं, इसलिए मैं कल संबंधित जानकारी जुटाऊंगा और उसके बाद इस विषय पर बात करूंगा.

गाजियाबाद के निवासी हैं युनुस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गांव के मूल निवासी यूनुस इकबाल शेख महाराष्ट्र चले गए. उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के फॉर्म-8 का इस्तेमाल करके और अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र से फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया. उनकी बेटी सहर शेख ने ठाणे मुंसिपल चुनाव के लिए मुंबई नगर निगम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया.

उन्होंने मुंबई के वार्ड 30 से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ठाणे नगर निगम का चुनाव जीता. उस समय 'कैसे हराया?' के अपने बयान से वह सुर्खियों में आईं. हालांकि, सहर शेख ने चुनाव लड़ते समय महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया है, और अब उनकी पार्षद पद से बर्खास्तगी की संभावना है.

सत्यापन के लिए दर्ज कराई थी शिकायत

सिद्दीकी फरहा शबाब अहमद ने ठाणे उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में यूनुस शेख के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए शिकायत दर्ज कराई थी. यूनुस ने अधिकारियों को गुमराह करते हुए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया, जबकि प्रवासियों के लिए फॉर्म-10 लागू था.

फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था. इसी आधार पर सहर ने मुंबई नगर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की जांच के बाद निरीक्षण की मांग की थी. ठाणे तहसीलदार को मिली शिकायत के अनुसार, यूनुस 18 मार्च को हुई सुनवाई में बीमारी का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे.

हालांकि, सुनवाई में उपस्थित उनके वकीलों ने जाति प्रमाण पत्र की रंगीन फोटोकॉपी और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए. सत्यापन के लिए 23 मार्च को दोबारा सुनवाई हुई. इस बार ठाणे तहसीलदार ने शेख के जाति प्रमाण पत्र में त्रुटियों की ओर इशारा किया, जबकि सहर शेख, ठाणे निवासी होने के बावजूद, मुंबई नगर कलेक्टर कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इरादे पर संदेह व्यक्त किया है.

मुंबई में खौफनाक ड्रग्स पार्टी, ओवरडोज से 2 छात्रों की मौत

युवती की हालत गंभीर, 6 लोग गिरफ्तार

मुंबई : मायानगरी मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में 11 अप्रैल को आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पार्टी उस वक्त मातम में बदल गई, जब ड्रग्स और शराब के कॉकटेल ने दो युवाओं की जान ले ली. पार्टी में ड्रग्स के ओवरडोज के चलते दो छात्रों की मौत हो गई है, जबकि एक 25 वर्षीय युवती की हालत बेहद गंभीर है और वह अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है. इस सनसनीखेज घटना के बाद मुंबई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

कैब में ली ड्रग्स, इवेंट में हुआ 'ओवरडोज'

जानकारी के मुताबिक, एक कॉलेज के करीब 15-16 स्टूडेंट्स का समूह इस म्यूजिक इवेंट में शामिल होने पहुंचा था. आरोप है कि पार्टी के दौरान खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री हुई. पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ युवाओं ने MDMA (एक्स्टेसी) जैसी हाई-प्रोफाइल ड्रग्स का सेवन किया था. सूत्रों के अनुसार, मृतकों में शामिल एक युवक ने इवेंट में आने से पहले कैब में ही ड्रग्स की एक गोली खा ली थी. इसके बाद इवेंट के दौरान उसने दूसरी डोज ले ली, जिससे शरीर में ओवरडोज की स्थिति बन गई.

सांस लेने में हुई तकलीफ और टूट गई सांसों की डोर

देर रात करीब 12 बजे पार्टी में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स को अचानक सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी. आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान एक युवक और एक युवती ने दम तोड़ दिया. इनकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है. डॉक्टरों ने भी शुरुआती तौर पर मौत की वजह ड्रग्स का 'ओवरडोज' ही बताया है, हालांकि अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद होगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:

विहान उर्फ आकाश सामल (31 वर्ष, इवेंट ऑर्गेनाइजर), सनी विनोद जैन, प्रतीक पांडे, आनंद पटेल, रौनक खंडेलवाल, बालकृष्ण कुरूप (सिक्योरिटी से जुड़ा) यह आरोपियों के नाम है.

इसके अलावा पुलिस ने दो कॉलेज स्टूडेंट्स और एक ड्रग सप्लायर को भी हिरासत में लिया है. सप्लायर के पास से 6-7 एक्स्टेसी (MDMA) टैबलेट्स भी बरामद की गई हैं. सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

इस मामले में पुलिस ने नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125, 125(B), 3(5) के साथ-साथ शराबबंदी कानून और NDPS एक्ट के तहत कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब तक 15 से 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. जांच में खुलासा हुआ है कि ड्रग्स मुंबई के बाहर से लाई गई थी.

इस खौफनाक घटना ने मुंबई पुलिस की एंटी-ड्रग्स मुहिम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इतने बड़े इवेंट में खुलेआम मौत का यह सामान कैसे बंटा और पुलिस व खुफिया विभाग को इसकी भनक समय रहते क्यों नहीं लगी? फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

अनिश्चय के भंवर में युद्धविराम का भविष्य

कुल ९३२ घंटे ३५ मिनट यानी ४० दिनों के युद्ध में खरबों की क्षति के बाद खाड़ी में अस्थायी दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान ने भी इसे कर लिया तथा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है कि वे ट्रंप के कदमों से सहमत हैं। हालांकि यह संघर्ष विराम है संघर्ष की समाप्ति नहीं। ईरान की ओर से कहा गया है कि उसने जो १० बदु दिए अमेरिका उन पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हमने जो १५ शर्तें रखीं उन पर ईरान विचार कर रहा है। यानी दोनों ने शर्तों को स्वीकारने की घोषणा नहीं की है। दूसरे, इजरायल ने ईरान पर हमले रोकने की बात स्वीकारते हुए कहा है कि लेबनान समझौते से बाहर है। ईरान के १० में लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले रोकने की शर्त भी रखी है। ट्रंप का कथन है कि युद्धविराम के बाद हम दीर्घकालिक शांति तथा पश्चिम एशिया के स्थायी समझौते की ओर बढ़ेंगे। क्या वाकई पश्चिम एशिया की जटिल समस्या का समाधान संभव है?

दुनिया भर में निहित स्वार्थी नैरेटिव चलाने पहले दिन से अमेरिका इजरायल को विश्व खलनायक एवं ईरान को योद्धा तथा निर्दोष पीड़ित साबित करते रहे हैं। सोच यह है कि ट्रंप को झुकना पड़ा एवं ईरान ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम माना तो साफ है कि ऐसे तत्व शांति नहीं कुछ और चाहते हैं। ट्रंप ६ अप्रैल को अपने पोस्ट में ईरान के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट धमकी दी थी कि अगर होर्मूज जलडमरूमध्य नहीं खोला तो एक ही पैकेज में उसके ऊर्जा संस्थान, आधारभूत संरचना, पुल सभी ध्वस्त होंगे। दिख रहा था कि ट्रंप दबाव की तरह भले धमकी का कर रहे हैं, वे युद्ध से वापसी भी चाहते थे, लेकिन उनके तेवर इतने कड़े थे और उन्होंने इसके प्रमाण दिए थे तो ईरान का अड़ियल रवैये पर पुनर्विचार करना स्वाभाविक था। ईरान अड़ता तो उसका विनष्ट होना निश्चित था। अगर भयानक रक्तपात व अनवरत युद्ध वाले पश्चिम समस्या का समाधान हो जाए तो विश्व में शांति स्थापना के ऐसे अध्याय की शुरुआत होगी जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। कतु तह साकार होता नहीं दिखता। इजरायल को लेकर ईरानी इस्लामी शासन की विचारधारा, व्यवहार, लेबानन, गाजा, इराक से यमन तक उसके द्वारा खड़े समूह की गतिविधियां, आंतरिक राजनीति तथा यहूदी इस्लाम के बीच मजहबी विवाद आदि को आधार बनाएं तो यह लक्ष्य अत्यंत कठिन है।

तत्काल इतना हुआ है कि ईरान ने परिस्थितियां देखकर होर्मूज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को स्वीकृति दी है कतु यह भी कहा है कि ईरानी सेना साथ समन्वय और तकनीकी शर्तों के आधार पर होगा। समस्या यही है। उसके सबसे बड़े सहयोगी चीन की समझाइस का तत्काल असर है। उसकी १० शर्तों में ईरान जलडमरूमध्य के नियमन और नियंत्रण का उसका अधिकार स्वीकार करना, प्रति जहाज २ करोड़ डॉलर टोल लेना भी शामिल है। हालांकि कहा है कि इसमें ओमान का भी हिस्सा होगा। उसने ईरान पर भविष्य में हमले न करने तथा सुरक्षा की गारंटी, उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति, युद्ध की पूरी क्षतिपूर्ति, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति की समाप्ति, लेबनान में सारे हमले रोकने आदि उसकी शर्तों है जो स्वीकार नहीं हो सकती। उसने नहीं कहा है कि हिजबुल्लाह, हमास या हुती इजरायल पर हमले रोक देंगे। बावजूद रोकने के बाद अमेरिका तुरंत हमला शायद ही करे।

२८ फरवरी को आरंभ युद्ध में ईरान को ऐसी अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी उसने दुःस्वप्नों में भी कल्पना की थी। यह इस युद्ध का कटु सच है जिसको नकारने के बाद आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। युद्ध में ३७२१ मौतें हुई। इनमें ईरान में सबसे ज्यादा २०७६, लेबनान में १४६१ और अरब देशों में १५६ लोग मारे गए। अरब में इराक में १०९, कुवैत में ७,बहरीन ३, सऊदी अरब में २, संयुक्त अरब अमीरात में १२, सीरिया में ४ और ओमान में ३ मौतें हुई। इसके समानांतर इजराइल में २६ लोग मारे गए तथा १३ अमेरिकी सैनिक भी। एक फ्रांसीसी सैनिक की मृत्यु हो गई। ईरान में कुल १३ हजार स्थानों पर बम गिरे हैं। कल्पना कि कैसा विध्वंस हुआ है। उसकी न्यूक्लियर क्षमता वाले स्थान ध्वस्त किए गए, मिसाइल बनाने के केंद्र काफी हद तक विनष्ट हुए, उसके लिए जो स्टील और अन्य सामग्रियां चाहिए वहां भी विध्वंस हुआ। जिन स्थानों में अंदर प्रवेश करना कठिन था उनके गेट या अन्य दिखने वाले जगहों बम गिराकर जितना ध्वस्त किया जा सकता था उतना करके छोड़ दिया गया।

आगे के लिए अमेरिका और इजरायल ने काफी विचार कर विनाश के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए थे जिनमें उसके महत्वपूर्ण बिजली केंद्र, पूल, संचार संस्थान, आवश्यक सेवाओं की आपूर्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। २८ फरवरी के हमले के बाद ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा आघात अयातुल्लाह अलखामेनेई, उनके परिवार व रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण सदस्य तथा सत्ता शीर्ष के एक साथ करीब तीन दर्जन लोगों का मार दिया जाना था। अचानक एक रिक्ति आ गई। यह ऐसे ही था जैसे एक साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके महत्वपूर्ण मंत्रियों तथा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सहित प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को मार डाले। बीच में जो भी सामने दिखता सेना प्रमुख, खुफिया प्रमुख, आईआरजीसी प्रमुख, पुलिस प्रमुख, बासित फोर्स प्रमुख, उनके उप प्रमुख, इनके उत्तराधिकारी सब जा रहे थे। मोजताबा खामेनेई को उत्तराधिकारी घोषित किया गया लेकिन अभी तक वे नहीं दिखे और जैसी सूचना है इतनी बुरी तरह घायल हुए हैं कि उनका उठना कठिन है।

पूरा कमान आईआरजीसी जैसी इस्लामी शक्तियों के हाथ था, जिसने अपने जवानों के एक इमाम के साथ नमाज पढ़ने वीडियो जारी किया। जिसका संदेश था कि हम इस्लाम के मुजाहिद हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं और हम शहीद होंगे तो मजहब के लिए जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। सूत्र नागरिक शासन के हाथों होता तो शायद संघर्ष राम पहले हो जाता। मसूद पेजेश्कियन ने सऊदी अरब, अरब अमीरात आदि पर मिसइल हमले के लिए क्षमा मांगी कतु उसके कुछ ही घंटे बाद फिर हमले हो गए। इससे साफ था कि इस्लामी क्रांति के बाद खामेनेई द्वारा सामान्य सेना, सुरक्षा, प्रशासन राजनीति के समानांतर शीर्ष भूमिका में मजहबी सेना - आंतरिक सुरक्षा, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्थायें की कमान उनके हाथों में है। यही भविष्य की शांति में सबसे बड़ी समस्या होगी। मजहब आने के बाद किसी भी मुस्लिम देश के साथ युद्ध को निर्णायक अवस्था में पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है।

समस्या का मूल ईरानी इस्लामी शासन द्वारा इजराइल के अस्तित्व को केवल करना ही नहीं उसे समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना है। इसके लिए यमन की हुती से लेकर गाजा में हमस, लेबनान में हिजबुल्ला ,इराक और अन्य जगह उसने आतंकवादी समूह खड़े किए और उनको सरेआम पूरी मदद देता है। यह संगठन मिसाइल और ड्रोन से हमले करते हैं। की इस्लामी व्यवस्था इजरायल को ही नहीं, संपूर्ण यहूदी समुदाय को इस्लाम का दुश्मन मानता है और उनकी सीधी घोषणा है कि आप हमारे हो या तुम्हारा पूरी तरह नाश करेंगे। इसमें इजरायल के सामने क्या विकल्प हो सकता है? ईरान पड़ोसी अरब देशों के विरुद्ध भी हमलावर रहता है युद्ध के दौरान उसने इजराइल से ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन हमले किए। अगर अमेरिका अकेले एकपक्षीय तरीके से ईरान से कोई समझौता करता है तो अरब देशों के सामने समस्या पैदा होगी। वे ईरानी सैन्य शक्ति के भय वाली स्थिति में रहना नहीं चाहते। सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, बहरीन ओमान, कुवैत, कतर सभी चाहते थे कि अमेरिका वहां लंबा युद्ध करे और ईरान को सैन्य और आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाकर समझौता करने के लिए मजबूर कर दे। अगर ईरान के स्थायी रुप से मजबूर होने की संभावना नहीं बनी तो ये देश भी अपनी शक्ति बढ़ाने जिसमें मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर शक्ति बनने का लक्ष्य शामिल होगा, दिशा में तेजी से अवसर होंगे। अरब के अनेक देशों ने इजरायल के अस्तित्व को घोषित या अघोषित स्वीकार कर लिया है। ईरान और उसके पोषित हथियारबंद समूह ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर हमले के समय पूर्व तक पूरे ईरान में हजारों लोग इस्लामी शासन के विरुद्ध सड़कों पर थे। उनको बेरहमी से कुचला गया, फांसी दी गई। मुद्रास्फीति १२०% से ऊपर चली गई थी।रियाल की कीमत डेढ़ लाख डॉलर तक थी। आज रियाल ०.००००७० भारतीय रुपये के बराबर है। देश में त्राहि-त्राहि थी। कुर्द, बलोच, अरबी आदि का विद्रोह अपनी जगह है। ईरान के कुह-ए- सियाह क्षेत्र में फंसे दो पायलटो को अमेरिका द्वारा छुड़ाने के बाद वहां के लोगों के विरुद्ध आईआरजीसी व पुलिस बलों की कार्रवाई जारी है। इस क्षेत्र के लोग इस्लामी गणराज्य के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। तो के अंदर आने वाले समय में बड़ा उबाल भी देखने को मिलेगा। मोजताबा खामेनेई सत्ता संभालने लायक नहीं हुये तो शीर्ष स्तर पर भी व्यापक सत्ता संघर्ष देखने को मिलेगा। इसमें संघर्ष विराम का भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है।

किशोर आक्रामकता एवं हिंसा पर अंकुश लगाने की पहल हो

ललित गर्ग

भारतीय किशोरों में बढ़ रही हसक प्रवृत्ति एवं क्रूर मानसिकता चिन्ताजनक है, नये भारत एवं विकसित भारत के भाल पर यह बदनुमा दाग है। पिछले कुछ समय से किशोरों में हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी, मर्मांतक एवं खौफनाक है। चता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में किशोरों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता एवं क्रूर मानसिकता घर करने लगी है और उनका हसक होता जा रहा है। बदलते समय के साथ समाज के व्यवहार में आई यह हसक तीव्रता और आक्रामकता अब केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सबसे चताजनक प्रभाव किशोर पीढ़ी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना ज्यादा परेशान करने वाला है। हाल के वर्षों में किशोरों किए गए अपराधों की संख्या और उनकी क्रूरता ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गया, बल्कि यह सामाजिक संरचना, पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभावों के गहरे संकट का संकेतक बन चुका है।

दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में मात्र चार रुपये के विवाद में एक युवक की नृशंस हत्या, जिसमें तीन किशोरों ने बेरहमी से चाकू घोंपे और चौथा उसका वीडियो बनाता रहा, इस विकृति का भयावह उदाहरण है। यह घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि संवेदनाओं के क्षरण, नैतिकता के पतन और कानून के भय के समाप्त हो का प्रतीक है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर किशोरों में यह दुस्साहस और हिंसात्मक प्रवृत्ति कहां से जन्म ले रही है? वस्तुतः, किशोर अपराधों के बढ़ते ग्राफ के पीछे कई परस्पर जुड़े हुए कारण हैं, जिनका विलेषण आवश्यक है। सबसे पहला और प्रमुख कारण है संरचना का विघटन। पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों को दादा-दादी, चाचा-चाची और अन्य सदस्यों के सान्निध्य में नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक मर्यादाओं का सहज प्रशिक्षण मिलता था। आज एकल परिवारों में माता-पिता की व्यस्तता और समयाभाव के कारण बच्चों के साथ संवाद का अभाव हो गया है। परिणामस्वरूप, किशोर समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं, जो कई बार उन्हें गलत दिशा में ले जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण है डिजिटल और सोशल मीडिया का अनियंत्रित प्रभाव। इंटरनेट ने जहां ज्ञान के द्वार खोले हैं, वहीं अपराध, हिंसा और अलीलता से भरी सामग्री भी किशोरों के लिए उपलब्ध कर दी है। फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी धारावाहिकों में हिंसा को जिस प्रकार ग्लैमराइज किया जाता है, वह किशोर मन को प्रभावित करता है। वे अपराध को एक साहसिक कार्य या रोमांच के रूप में देखने लगते हैं। कई बार वे यह भूल जाते हैं कि वास्तविक में इसके गंभीर और जीवन विनाशक घातक परिणाम होते हैं। तीसरा पहलू शिक्षा व्यवस्था का है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा और रोजगार तक सीमित हो गया है। नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षण लगभग समाप्त हो गया है। शिक्षकों की भूमिका भी अब की बजाय केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक सीमित हो गई है। विद्यालयों में अनुशासन और संवाद का जो वातावरण होना चाहिए, वह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समाज में बढ़ती असहिष्णुता और आक्रामकता भी किशोरों को प्रभावित कर रही है। जब वे अपने आसपास छोटे-छोटे विवादों लोगों को हसक होते देखते हैं, तो यह उनके लिए सामान्य व्यवहार बन जाता है। राजनीति, मीडिया और सामाजिक जीवन में बढ़ती कटुता और टकराव की प्रवृत्ति किशोरों के मन में भी उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। किशोर अपराधों के पीछे एक और गंभीर कारण है आपराधिक द्वारा उनका उपयोग। चूंकि कानून में किशोरों के लिए अपेक्षाकृत नरमी होती है, इसलिए अपराधी गिरोह उन्हें अपने कार्यों के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी किशोरों को अपराध की ओर धकेलती है। नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी, लूट और यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराध करने से भी नहीं हिचकते।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि किशोर न्याय से जुड़े कानूनों का लचीलापन कई बार अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के बावजूद किशोरों को शीघ्र कर दिया जाता है, जिससे उनमें कानून का भय समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में यह बहस भी समय-समय पर उठती रही है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त किशोरों के लिए वयस्कों जैसा दंड प्रावधान होना चाहिए या नहीं? हालांकि केवल कानून को कठोर बनाना ही समाधान नहीं समस्या की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले परिवार को अपनी भूमिका को पुनः समझना होगा। बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना, उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना और उन्हें सही-गलत का अंतर समझाना अत्यंत आवश्यक है। माता-पिता यह समझना होगा कि केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय और संस्कार देना अधिक महत्वपूर्ण है।

दूसरे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और व्यवहारिक प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षकों को केवल प्रदाता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। स्कूलों में काउंसलग व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है ताकि किशोर अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। तीसरे, मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। हिंसा और अपराध को महिमामंडित करने के बजाय सकारात्मक प्रेरणादायक सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण को सख्ती से लागू करना होगा। चौथे, पुलिस और प्रशासन को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, अपराध की रोकथाम पर अधिक ध्यान होगा। समुदाय आधारित पुलिसग, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और किशोरों के साथ संवाद जैसी पहलें प्रभावी हो सकती हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में ३५.८ प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। मोबाइल व कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बह रहे नीले जहर से किशोर अराजक यौन व्यवहार एवं हसक प्रवृत्तियों की तरफ उन्मुख हुए हैं। को समझाने वाला कोई नहीं है कि यह रास्ता आत्मघात का है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन जैसे देश किशोरों को मोबाइल से दूर रखने हेतु कानून बना रहे हैं। हमारे देश में भी शीर्ष अदालत ने समय-समय पर ऐसी घटनाओं पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। क्या इन दर्दनाक घटनाओं हमारे अभिभावकों, समाज-निर्माताओं एवं हमारे सत्ताधीशों की आंख खुलेगी? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी सहम गयी है। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास एवं नयी समाज-व्यवस्था की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी की हत्या तक कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

यदि एक किशोर अपराध की राह पर जाता है, उसमें कहीं न कहीं परिवार, समाज, शिक्षा और व्यवस्था की भी जिम्मेदारी होती है। आज आवश्यकता है एक समन्वित और संवेदनशील दृष्टिकोण की, जिसमें सरकार, समाज, परिवार और शिक्षा संस्थाएं मिलकर कार्य करें। केवल दंड से नहीं, बल्कि संवाद, संस्कार और सकारात्मक मार्गदर्शन से ही इस समस्या का स्थायी संभव है। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह आक्रामकता आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी गंभीर संकट का रूप ले सकती है। इसलिए यह समय चेतने का है, सोचने का है और मिलकर समाधान खोजने का है, ताकि हमारी किशोर पीढ़ी की राह छोड़कर सृजन और संवेदना के मार्ग पर अग्रसर हो सके।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
दिल्ली- ९८११०५११३३

अब फार्मर आईडी से ही मिलेगा खाद

नई दिल्ली : सरकार ऋफार्मर आईडीऋ के आधार पर यूरिया और अन्य खाद का वितरण करेगी, जिससे औद्योगिक डायवर्जन और ब्लैक मार्केटग रुकेगी. ४१,००० करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ की कीमतें स्थिर रखी गई हैं.

यूरिया के बढ़ते डायवर्जन को रोकने और इसे केवल खेती तक सीमित रखने के लिए सरकार अब खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नई व्यवस्था के तहत किसानों को यूरिया और अन्य खाद अब सिर्फ 'फार्मर आईडी' के आधार ही दिए जाएंगे. अब तक देशभर में करीब ९ करोड़ ३० लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर १३ करोड़ तक पहुंचाने का है.

इस नई सिस्टम की टेस्टिग मध्य प्रदेश और हरियाणा में सफलतापूर्वक की जा चुकी है. सरकार का मानना है इस कदम से यूरिया का गलत इस्तेमाल, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाला डायवर्जन, काफी हद तक रोका जा सकेगा. साथ ही इससे असली किसानों को समय पर और सही मात्रा में खाद मिल पाएगी, जिससे खेती की उत्पादकता में भी सुधार होने की उम्मीद है.फर्टिलाइजर व्यवस्था पर सरकार कहा कि कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद ये फैसला किया गया है

कि यूरिया की बोरी २६६ रुपये और डीएपी की बोरी १३५० रुपये में ही किसानों को मिलेगी. इसके लिए हाल ही में कैबिनेट ने ४१,००० करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है, ताकि बढ़ी लागत का पूरा बोझ सरकार उठाए और किसान पर भार न पड़े. सरकार ने कहा कि सब्सिडी वाला खाद कई बार दूसरे उद्योगों या गैरकृषि उपयोग में डायवर्ट हो जाता है.

इसे रोकने के लिए फार्मर आईडी आधारित मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत हर किसान की फसल और परिवार का डेटा एक एकीकृत आईडी से जुड़ा होगा.

फार्मर आईडी के आधार पर यह तय होगा कि कितनी जमीन और कौनसी फसल के लिए कितना खाद पर्याप्त है, ताकि किसान को कमी न हो, इसके अलावा खाद की अतिरिक्त उठाव, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटग पर रोक सरकार ने बताया कि अब तक ९ करोड़ २९ लाख से अधिक फार्मर आईडी बन चुकी हैं और लक्ष्य है कि इसे लगभग १३ करोड़ किसानों तक विस्तारित किया जाए. जहां बटाई या पट्टे पर खेती की परंपरा है, वहां जमीन मालिक के लिखित प्रमाण के आधार पर बटाईदार को भी खाद उपलब्ध कराने का मॉडल मध्य प्रदेश और हरियाणा में सफल रहा है. जिसे और परिष्कृत कर देशभर में लागू करने पर काम हो रहा है।

प्राकृतिक खेती पर सरकार ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ष १ करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति संवेदनशील करने कम से कम १८ लाख किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने का लक्ष्य रखा था।

जिसमें से लगभग १८ लाख किसानों और करीब ८ लाख हेक्टेयर जमीन पर प्रमाणित प्राकृतिक खेती की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. वहीं, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यदि प्राकृतिक खेती की पद्धतियां सही से अपनाई जाएं, तो उत्पादन घटे बिना लागत में कमी की जा सकती है और इससे फर्टिलाइजर आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक हालात के बीच भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए राहत भरा कदम उठाया है. सरकार ने उर्वरक उद्योग मिलने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाकर पिछले छह महीनों की औसत खपत के करीब ९५ प्रतिशत तक पहुंचा दी है, ताकि आने वाले खरीफ सीजन से पहले खाद उत्पादन पर किसी तरह का दबाव न बने. सरकार ने कहा कि गैस सप्लाई बढ़ने से यूरिया और अन्य उर्वरकों उत्पादन में कोई बाधा नहीं आएगी. खरीफ सीजन से पहले अप्रैल और मई को खाद उत्पादन के लिए अहम समय माना जाता है, ऐसे में यह फैसला किसानों के लिए भी राहत भरा है. सरकार ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बावजूद देश में ऊर्जा और खाद की को स्थिर रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और गैस, एलपीजी व अन्य ईंधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.

सरकार देश में टिकाऊ और सुरक्षित कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पर लगातार दे रही है. इसका उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके मिट्टी की सेहत सुधारना, किसानों की लागत घटाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है. भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें परंपरागत कृषि योजना प्रमुख है. इस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और प्रमाणन की सुविधा दी जाती है.

इसके अलावा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.

किसानों को गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है. साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटग के लिए जैविक भारत ब्रांड और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके. दें कि जैविक खेती के कई फायदे हैं. इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, पानी की क्वालिटी बेहतर होती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है. साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी इजाफा हो सकता.

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल की आर्थिक हालत पर सरकार सख्त

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की आर्थिक हालत को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है. वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि लालपरी अभी भी घाटे के बोझ से जूझ रही है. इसी को लेकर परिवहन मंत्री और महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घाटा कम करने के लिए बड़े स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं.

एसटी महामंडल के मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि इस वित्त वर्ष में कुल परिचालन राजस्व 11,475 करोड़ रुपये रहा, जबकि खर्च 12,066 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसका सीधा मतलब है कि महामंडल को 591 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा.

अगर रोजाना के हिसाब से देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है. रोज औसतन 31 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई हो रही है, जबकि खर्च करीब 33 करोड़ रुपये है. यानी हर दिन करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये का घाटा हो रहा है.

ज्यादातर विभाग घाटे में

राज्य के कुल 31 विभागों में से सिर्फ 8 ही मुनाफे में हैं, जबकि 23 विभाग लगातार घाटे में चल रहे हैं. पिछले वित्त वर्ष में जालना, परभणी, बुलढाणा, भंडारा, गडचिरोली, अकोला, धुले और वर्धा जैसे विभाग लाभ में रहे थे. लेकिन नाशिक, कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी, सातारा और ठाणे जैसे बड़े विभागों में बढ़ता घाटा सरकार के लिए चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है. बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, "आने वाले वित्त वर्ष में परिवहन का उचित नियोजन कर उपलब्ध बसों और मानव संसाधनों का अधिकतम कुशल उपयोग करना आवश्यक है. प्रतिदिन डेढ़ से 2 करोड़ रुपये के घाटे को कम करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए."

घाटे वाले विभागों की होगी गहन जांच

मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि जो विभाग लगातार नुकसान में चल रहे हैं, उनकी गहराई से जांच की जाए. घाटे के कारणों का विश्लेषण कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है. साथ ही बड़े घाटे वाले विभागों में सक्षम और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति पर जोर दिया जाएगा.

पवार परिवार में सुप्रिया सुले सबसे अमीर, उनके बाद हैं सुनेत्रा, तीसरे नंबर पर खिसके शरद पवार

पुणे : अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती विधानसभा सीट के लिए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एनसीपी-एसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी की सदस्य कांग्रेस ने चुनाव मैदान में प्रवेश किया है। इस बीच सुनेत्रा पवार के चुनावी हलफनामों से पता चला है कि एनसीपी(SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पवार परिवार में सबसे अमीर हैं। जबकि उनके पिता और पार्टी प्रमुख शरद पवार इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनावी हलफनामों के अनुसार, सुप्रिया सुले के पास 167 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति है। जो कि शरद पवार की संपत्ति से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। शरद पवार के पास 61 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वहीं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास 122 करोड़ रुपये की संपत्ति है। ये आंकड़े बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान सामने आए। इससे चुनाव में परिवार बनाम संपत्ति को लेकर बहस तेज हो गई है।

सुनेत्रा पवार के पास कितनी दौलत?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनावी हलफनामों के अनुसार, सुप्रिया सुले के पास 167 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति है। जो कि शरद पवार की संपत्ति से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। शरद पवार के पास 61 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वहीं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास 122 करोड़ रुपये की संपत्ति है। ये आंकड़े बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान सामने आए। इससे चुनाव में परिवार बनाम संपत्ति को लेकर बहस तेज हो गई है।

सिर्फ़ फल खाने से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके कुछ नुक़सान भी हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में औसतन हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है. वर्ष २०२५ में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के अनुसार, १९९० से ३५ वर्षों की अवधि में दुनिया में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि किशोरों में यह वृद्धि चौगुनी हो गई.

विशेषज्ञों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के आहार और शारीरिक गतिविधि में असंतुलन होता है, तो उसका वज़न बढ़ जाता है या वह मोटापे का शिकार हो जाता है.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अधिकतर मामलों में पर्यावरण, मनोदशा और आनुवंशिक जैसे कई कारण मोटापे को प्रभावित करते हैं. लोग अपने आहार में बदलाव करके मोटापे से बचने के लिए अलग-अलग तरीक़े अपनाते हैं.

एक तरीक़ा फ्रूटेरियनिज़्म है, जिसमें व्यक्ति केवल फल, सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार के सूखे बीज खाता है. हालांकि कई लोग मानते हैं कि केवल फल खाने से वज़न कम करने में मदद मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में हेल्दी विकल्प है?

तमिलनाडु के इरोड के डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि यह सच है कि केवल फल खाने से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है.

इसका कारण बताते हुए डॉ. अरुण कुमार कहते हैं, "जो लोग केवल फल खाते हैं, उन्हें अपनी दैनिक कैलोरी का ८० से ९० प्रतिशत हिस्सा फलों से मिलता है. आमतौर पर फलों में कैलोरी कम होती है और उनसे अधिकतम लगभग १५०० कैलोरी ही प्राप्त की जा सकती है."

"इससे कैलोरी की कमी होती है और वज़न कम होता है. हालांकि, केवल फल खाने से शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, जिससे मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं."

इसके अलावा, केवल फल खाने से शरीर को आयरन, जिंक और ओमेगा-३ जैसे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं. इससे शरीर में फ्रक्टोज़ (एक प्रकार का प्राकृतिक शुगर) का स्तर बढ़ सकता है. साथ ही, ट्राइग्लिसराइड्स (एक प्रकार का फ़ैट) और लिवर में फ़ैट की मात्रा भी बढ़ सकती है.

डॉ. अरुण कुमार का कहना है कि सिर्फ़ फल खाना वज़न घटाने का सही तरीका नहीं है. वे वज़न घटाने के लिए खुराक में पर्याप्त मात्रा में फल शामिल करने की सलाह देते हैं, लेकिन केवल फल पर निर्भर रहने को ख़तरनाक मानते हैं.

कई अध्ययनों से पता चला है कि केवल फल, मेवे या बीज खाने से अलग-अलग पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

अमेरिकी गैर-लाभकारी चिकित्सा संगठन मेयो क्लिनिक के अनुसार, केवल फल खाने से प्रोटीन, आवश्यक वसा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी१२ जैसे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं. इससे मांसपेशियां और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है. साथ ही एनीमिया का ख़तरा बढ़ जाता है.

जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ़ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अनुसार, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो इसका सीधा प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है. यह शरीर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित खुराक की अहमियत को दिखाता है.

क्या चिकन और मटन खाने से मोटापा बढ़ता है?

चिकन और मटनल में प्रोटीन की अधिकता होती है, जिससे फ़ैट कम करने में मदद मिल सकती है. ऐसी मान्यता है कि ज़्यादा चिकन और मटन खाने से मोटापा बढ़ता है. क्या इसमें कोई सच्चाई है?

डॉ. अरुण कुमार कहते हैं, "अगर चिकन और मटन का सेवन सही मात्रा में किया जाए, तो इससे वज़न कम करने में मदद मिल सकती है."

"अतिरिक्त कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन स्राव को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में फ़ैट जमा होने लगती है. कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन पेट के आसपास फ़ैट जमा होने का कारण बनता है."

"कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी से भरपूर और इंसुलिन स्राव बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट के आसपास फ़ैट जमा हो जाती है."

उन्होंने कहा कि अगर चिकन और मटन जैसे खाद्य पदार्थों का सही मात्रा में सेवन किया जाए, तो यह वज़न घटाने के लिए एक उपयुक्त आहार हो सकता है. वो वज़न घटाने के लिए मांस सहित कम कैलोरी वाले हेल्दी खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं.

बदबू का आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है?

आपकी ओर आती हुई बदबू सिर्फ आपको उबकाई ही नहीं दिलाती, यह आपके शरीर और दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है.

हम सभी ने कचरा फेंकते समय सड़ते हुए कचरे की बदबू महसूस की है, कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हुए या किसी फैक्ट्री से आने वाली खराब गंध का सामना किया है. जरा सोचिए, अगर आपको लगातार ऐसी बदबू के साथ रहना पड़े, तो क्या होगा?

फिर भी हम इस तरह के 'गंध प्रदूषण' के सेहत पर असर के बारे में बहुत कम ध्यान देते हैं. ख़राब गंध को अक्सर व्यक्तिगत या मामूली मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है.

लोग आमतौर पर अपनी सूंघने की क्षमता को देखने, सुनने, छूने और स्वाद से कम अहमियत देते हैं. अमेरिका के कुछ कॉलेज छात्रों ने तो यह भी माना कि वे अपनी सूंघने की क्षमता खोने के बजाय अपना फोन खोना पसंद करेंगे. यह सिर्फ असुविधा की बात नहीं है जो लोग खराब गंध के साथ रहने पर महसूस करते हैं. अध्ययन बताते हैं कि शहरी इलाक़ों में अप्रिय गंध सिरदर्द, मतली, सांस लेने में कठिनाई या नींद में बाधा जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी होती हैं. इनका मानसिक और शारीरिक असर लंबे समय तक रह सकता है.

ख़तरे की गंध

सूंघने की क्षमता आंशिक रूप से एक शुरुआती चेतावनी संकेत के रूप में विकसित हुई है, ताकि हम बीमार या संक्रमित होने से बच सकें. जो चीज सड़ी हुई गंध देती है, उसमें अक्सर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं. स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट में गंध विज्ञान के प्रोफेसर जोहान लुंडस्ट्रॉम कहते हैं कि सूंघने की क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है.

लुंडस्ट्रॉम कहते हैं, "ये एक बचाव प्रणाली की तरह काम करती है, जो हमें पर्यावरण में ख़तरे के बारे में चेतावनी देना सिखाती है."

उनके शोध से यह भी पता चला है कि गंध के संकेत नाक के ज़रिए अंदर जाने के लगभग ३०० मिलीसेकंड के भीतर दिमाग में प्रोसेस हो जाते हैं. शोध के दौरान ख़राब गंध के संपर्क में आए लोगों ने तेज शारीरिक प्रतिक्रिया दिखाई और स्वाभाविक रूप से बदबू वाली जगह से दूर हट गए.

सूंघने की यह रक्षात्मक प्रवृत्ति किसी को यह यक़ीन दिलाना आसान बना देती है कि कोई गंध खराब है, भले ही वह सामान्य रूप से अच्छी मानी जाती हो.

सेहत पर असर

सूंघना सिर्फ ख़तरे का पता लगाने तक सीमित नहीं है. गंध का लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है. वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अच्छी गंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यह दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो भावनाओं और यादों से जुड़े होते हैं.

यह भी प्रमाण हैं कि इसके विपरीत, खराब गंध हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, हालांकि वैज्ञानिक अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 'गंध प्रदूषण' और सीधे शारीरिक प्रभाव के बीच सटीक संबंध क्या है.

२०२१ के एक अध्ययन में पाया गया कि खराब गंध से सिरदर्द या उल्टी जैसे लक्षणों के पीछे कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं. उदाहरण के लिए, खराब गंध 'वेगस नर्व' को सक्रिय कर सकती है, जो दिमाग

और आंत को जोड़ने वाली तंत्रिका प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे व्यक्ति को मतली महसूस हो सकती है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए और शोध की ज़रूरत है.

हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस गंध को लेकर कितने चिंतित हैं.

अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित 'मोनेल केमिकल सेंस सेंटर' की मनोवैज्ञानिक पामेला डाल्टन कहती हैं, "स्वास्थ्य पर प्रभाव व्यक्ति की उस गंध के प्रति नापसंद या डर के जरिए होता है."

उन्होंने ३२ साल तक गंध के स्वास्थ्य प्रभावों का अध्ययन किया है. जितना अधिक आप किसी गंध को लेकर चिंतित होते हैं, उतना ही यह आपके स्वास्थ्य और जीवन पर असर डालती है.

जीवनशैली में बदलाव

लगातार रहने वाली ख़राब गंध जीवन के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है. यह लोगों को जीवनशैली में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. इन्हें "मैलएडैप्टिव एक्शंस" कहा जाता है.

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गर्मियों में भी खिड़कियां बंद रखने या बाहर जाकर व्यायाम करने या दोस्तों के साथ समय बिताने से कतरा सकता है. फिर भी, कुछ लोगों के लिए हल्की सी बदबू भी असहनीय हो सकती है. लेकिन उम्र, लिंग, एलर्जी और धूम्रपान जैसी जीवनशैली से जुड़े विकल्प भी यह तय करते हैं कि लोग गंध को कैसे महसूस करते हैं. ये संभव है कि लोग समय के साथ खराब गंध के आदी हो जाएं लेकिन लैंडफिल जैसी गंध को सहना जरूरी नहीं कि आसान हो जाए. इसके विपरीत, सामान्य या अच्छी गंध के प्रति अभ्यस्त होना सामान्य है.

लुंडस्ट्रॉम कहते हैं, "एक बार जब आप किसी गंध को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो आप उसे महसूस करना बंद कर देते हैं."

यही वजह है कि इंसान की नाक एक ट्रिलियन गंध पहचान सकती है, फिर भी लोग उन चीजों की गंध का नाम बताने में कठिनाई महसूस करते हैं जो खतरनाक नहीं हैं.

शोध से पता चलता है कि हममें से आधे से भी कम लोग कॉफी या वनीला जैसी रोजमर्रा की गंध को सही पहचान पाते हैं.

कभी-कभी अक्सर हवा की दिशा के साथ बदबू आती-जाती रहती है या किसी इलाक़े के कुछ हिस्सों में ही महसूस होती है.

गंद से लडाई

कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पर्यावरण मॉडलिंग और नीति की एसोसिएट प्रोफेसर अमांडा जियांग कहती हैं, "गंध बहुत स्थानीय हो सकती है. मैं एक ब्लॉक दूर रह सकती हूं

और मुझे पता ही न चले कि पास वाला इलाका सड़ी मछली जैसी गंध दे रहा है."

उन्होंने वैंकूवर में गंध प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन किया है. लेकिन हर कोई इस बदबू को समान रूप से अनुभव नहीं करता. शहरों के कम आय वाले इलाके अक्सर बदबूदार लैंडफिल साइट्स या भारी उद्योगों के पास होते हैं.

यूरोप और ब्रिटेन में किए गए अध्ययन बताते हैं कि कुछ देशों में कचरा जलाने वाले प्लांट, लैंडफिल और ख़तरनाक कचरा स्थलों के पास कम आय वाले लोगों के रहने की अधिक संभावना है.

खराब गंध को लेकर शिकायतें बदलाव ला सकती हैं. सीवेज प्लांट से लेकर मछली प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों तक, कई जगहों को स्थानीय लोगों के अभियान के बाद बंद करना पड़ा है. दुनिया भर में गंध प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास बढ़ रहे हैं, हालांकि यह समान रूप से नहीं हैं.

उदाहरण के लिए, चिली में मछली चारे के प्लांट से आने वाली गंध पर नया नियम लागू किया गया है, जबकि लिथुआनिया में आवासीय इलाकों में कंपनियों की पैदा की जाने वाली बदबू की सीमा तय करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं.

गंध के फ़ायदे

जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां खराब गंध होती है, उनके लिए जीवन मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बात सकारात्मक है कि अच्छी तरह काम करने वाली सूंघने की क्षमता अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

शोध से पता चलता है कि जिन लोगों की सूंघने की क्षमता तेज होती है, वे खाने और यहां तक कि यौन जीवन का भी अधिक आनंद लेते हैं.

२०१८ के एक अध्ययन में ७० वयस्कों पर किए गए शोध में पाया गया कि जिन लोगों की सूंघने की क्षमता बेहतर होती है उन्हें सेक्स से अधिक संतुष्टि मिलती है. इसी शोध के मुताबिक महिलाओं ने सेक्स के दौरान अधिक बार ऑर्गैज्म होने की बात मानी. पामेला डाल्टन कहती हैं, "मुझे खराब गंध से परेशानी नहीं होती क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी सूंघने की क्षमता अच्छी तरह काम कर रही है."

दुनिया में पाँच प्रतिशत लोगों में सूंघने की क्षमता नहीं होती. इस स्थिति को एनोस्मिया कहा जाता है. ऐसे लोगों को कई तरह के स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ता है.

ऐसे लोगों से बातचीत में पता चलता है कि उन्हें भूख कम लगती है और खाने का आनंद न ले पाने के कारण उनका डायट भी गड़बड़ा सकती है.

लुंडस्ट्रॉम कहते हैं, "अगर आप अपनी सूंघने की क्षमता खो देते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपकी भूख कम हो गई है."

शोध से पता चलता है कि बुज़ुर्गों में सूंघने की कमज़ोर क्षमता १० साल के भीतर मृत्यु के जोखिम को ४६% तक बढ़ा सकती है. वैज्ञानिक अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि इसका संबंध हृदय रोग, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों से जोड़ा जा रहा है.

सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद?

गर्म या गुनगुना पानी पीने के फ़ायदों को हज़ारों सालों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा और भारत में शुरू हुए आयुर्वेद में बताया जाता रहा है.

लेकिन साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, ये पुरानी आदत अब दुनिया भर में लोगों तक पहुंच गई है. ज़्यादातर युवा लोग गर्म पानी पीते, गर्म नाश्ता करते और स्ट्रेचिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते दिखते हैं. लेकिन क्या ये आसान आदतें सच में आपकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं?

चीन में लाखों लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक चिकित्सा की एक मुख्य मान्यता यह है कि शरीर में ऊर्जा यानी 'ची (Qi)' बहती रहती है. जब इस ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या असंतुलित हो जाता है, तो बीमारी होती है. इस विचार को मानने वाले लोगों का कहना है कि गुनगुना पानी पीना, 'ची' को बढ़ाता है और उसे संतुलित रखता है. पानी को मुंह या गले को जलने से बचाने के लिए ४० से ६० डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर रिसर्च करने वाले प्रोफ़ेसर शुन आउ कहते हैं, "इसे एक घर की तरह समझिए."

उनका कहना है कि इस समग्र स्वास्थ्य पद्धति में ठंडा खाना घर में ठंडी हवा का झोंका आने जैसा है.

यही सोच पारंपरिक चीनी चिकित्सा की दूसरी सलाहों, जैसे घर में गर्म चप्पल पहनना और दिन की शुरुआत गर्म नाश्ते से करने का भी आधार है.

लंदन में रहने वालीं ख़ान ने इस ट्रेंड को सबसे पहले टिकटॉक पर देखा था. वो एक आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हैं. उनके लिए ये आदतें पारंपरिक चीनी चिकित्सा को अपनाने की शुरुआत बनीं.

वह कहती हैं कि ताइ-ची से दिन की शुरुआत करने से उन्हें फ़ायदा महसूस हो रहा है. ताइ-ची में धीमी, सहज हरकतें, गहरी सांसें और मेडिटेशन शामिल होता है. साथ ही लोग अपनी रोज़ की कॉफी की जगह गुनगुना पानी पीते हैं.

वह कहती हैं, "सुबह-सुबह मैंने सादा गर्म पानी और कभी-कभी उसमें पुदीना या नींबू डालकर पीना शुरू किया. और इससे मुझे ज़्यादा ताज़गी महसूस हुई."

विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की अंतरिम निदेशक डॉ. श्यामा कुरुविला कहती हैं कि पारंपरिक चीनी जीवनशैली से जुड़ी टिप्स में युवाओं की ऑनलाइन रुचि, समाज में बढ़ते एक नए ट्रेंड को दिखाती है.

उन्होंने बताया कि, "यूरोप में भी इस पर आबादी-आधारित अध्ययन हुए हैं. जर्मनी के एक अध्ययन में पाया गया कि ७० फ़ीसदी या उससे ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा को पूरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. साथ ही चीन और भारत जैसे कुछ देशों में ये आंकड़ा ९० फ़ीसदी से भी ज़्यादा हो सकता है."

कुछ लोग आधुनिक चिकित्सा पर भरोसा नहीं करते. हो सकता है कि ये सोच कोरोना महामारी के बाद और बढ़ी है. अमेरिका के एक अध्ययन के मुताबिक, साल २०२० में डॉक्टरों और अस्पतालों पर भरोसा ७० फ़ीसदी से ज़्यादा था, जो २०२४ तक घटकर करीब ४० फ़ीसदी रह गया.

कुछ लोग पारंपरिक चिकित्सा की ओर इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और समग्र इलाज का तरीका होता है. गर्म पानी पीने जैसी आदतें ऐसे स्वास्थ्य पद्धति की शुरुआत बन सकती हैं, जो मन, शरीर और वातावरण के संतुलन पर ज़ोर देते हैं.

इन चिकित्सा पद्धतियों का कई लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी होता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर सबूतों का मूल्यांकन करता है, ताकि नीति-निर्माताओं और मरीजों को सही मार्गदर्शन दिया जा सके.

क्योंकि अभी दुनिया भर के हेल्थ रिसर्च फंड का १ फ़ीसदी से भी कम हिस्सा पारंपरिक चिकित्सा पर खर्च होता है. "इस क्षेत्र में ठोस सबूतों को और मज़बूत करने की ज़रूरत है."

डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ का कहना है कि पारंपरिक चिकित्सा अपनाने से पहले मरीजों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि यह उनके इलाज के हिसाब से सुरक्षित हो.

WHO की इस पर कोई खास गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कुरुविला कहती हैं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी कितना गर्म है, आप कितना पीते हैं और आपकी सेहत कैसी है. वह ज़ोर देकर कहती हैं, "सब कुछ सबूत और संतुलन पर ही निर्भर करता है."

कामेच्छा कम हो रही है? इसे बेहतर किया जा सकता है

९० के दशक में, एलन रीव्स नियमित रूप से मंच पर परफ़ॉर्म करते थे और 'द ड्रीमबॉयज़' के सदस्य के रूप में हज़ारों लोगों के सामने अपने कपड़े उतारते थे. उस समय २४ साल के रीव्स, ख़ुद उनके ही शब्दों में, 'एक तरह के पिन-अप' या चर्चित पोस्टर बॉय थे. लेकिन जब रीव्स ३० साल से ज़्यादा उम्र के हुए तो उन्होंने ख़ुद को एक बहुत ही अलग स्थिति में पाया- उनका मूड ख़राब रहने लगा था और उनकी कामेच्छा लगभग ग़ायब हो चुकी थी.

वह कहते हैं, "मुझे बस कुछ सही नहीं लग रहा था." अब ५२ वर्ष के हो चुके रीव्स कहते हैं कि सेक्स ड्राइव की कमी का उनके लंबे समय के रिश्ते पर बुरा असर पड़ने लगा था. अब लंदन में एक फ़िटनेस और लाइफ़स्टाइल कोच के रूप में काम कर रहे रीव्स ने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू की और उनका कहना है कि इसने उन्हें उनकी कामेच्छा वापस दिला दी है.

इसी पृष्ठभूमि में, एक बहस ज़ोर पकड़ रही है. क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना कामेच्छा में सुधार कर सकता है, या इस पर मिल रहा अधिकांश ध्यान केवल दिखावा, मुनाफ़ा और भ्रम है?

वास्तव में, सेक्स की आवृत्ति में सबसे तेज़ गिरावट अधिक उम्र के विवाहित या साथ रहने वाले जोड़ों में देखी गई. क्लिफ्टन का कहना है कि साफ़-साफ़ यह कहना मुश्किल है कि सेक्स ड्राइव क्यों कम हो रही है.

वह कहती हैं, "हमारे पास अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं है जो हमें पूरे भरोसे के साथ बता सके कि एक आबादी के तौर पर हम अब पहले जितना सेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं."

ये अध्ययन बताते हैं कि डिजिटल दुनिया एक बड़ा कारक हो सकती है, जिसकी वजह से स्क्रीन को स्विच ऑफ़ करना मुश्किल हो गया है, साथ ही अब समय बिताने के लिए और भी बहुत से विकल्प मौजूद हैं. जनरल फ़िज़िशियन (जीपी) और सेक्स थेरेपिस्ट डॉक्टर बेन डेविस कहते हैं कि हमारे तनाव का स्तर भी आम तौर पर ३० साल पहले की तुलना में अधिक है, और यह भी एक कारण हो सकता है.

वह कहते हैं, "लोगों के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है. ज़ाहिर है कि तकनीक तो है ही, लेकिन तनाव, अवसाद और अकेलेपन में भी वृद्धि हुई है. ये सभी चीज़ें सेक्स ड्राइव में कमी का कारण बनती हैं."

"मोटापे में वृद्धि, टाइप २ डायबिटीज़, और गतिहीन जीवन शैली जीने वाले लोगों की बढ़ती संख्या- ये सभी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करते हैं. और गिरता हुआ टेस्टोस्टेरोन स्तर हमारी सेक्स ड्राइव में कमी का एक कारण होगा." तो, क्या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वास्तव में कम कामेच्छा का रामबाण इलाज हो सकती है?

टेस्टोस्टेरोन ने 'मेरी ज़िंदगी वापस लौटा दी'

मेलिसा ग्रीन पिछले लगभग एक साल से टेस्टोस्टेरोन ले रही हैं. उनका कहना है कि इसने न केवल उन्हें 'जीने का उत्साह' वापस दिया है, बल्कि उनकी शादी भी बचा ली.

पेरिमेनोपॉज़ल (रजोनिवृत्ति के शुरुआती लक्षण) होने के कारण, उनके जीपी ने उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ज़रिए पहले से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिखकर दिया था, लेकिन ग्रीन का कहना है कि डॉक्टर उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तर की जांच करने को तैयार नहीं थे. उनका कहना यह था कि उन्हें इस अतिरिक्त हार्मोन की ज़रूरत नहीं है.

महिलाओं के शरीर में यह हार्मोन कम मात्रा में बनता है, और एनएचएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन तब दिया जा सकता है जब उन्हें 'हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर' हो, यानी उनकी सेक्स ड्राइव बहुत कम या न के बराबर हो. यह किसी भी उम्र की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) के आस-पास यह अपने चरम पर होता है. जहां कुछ लोग सेक्स ड्राइव पर टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं, वहीं अन्य का कहना है कि इसके कुछ अप्रिय प्रभाव भी हुए हैं.

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

आईपीएल २०२६

पंजाब ने मुंबई को रौंदा

बुमराह-हार्दिक का फ्लॉप शो

मुंबई : वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल २०२६ के २४ वें मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को ७ विकेट से हरा दिया है. मुंबई ने पहले खेलने के बाद १९५ रन बनाए थे. जवाब में पंजाब किंग्स ने १७ वें ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने ३५ गेंद में ६६ रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने ३९ गेंद में नाबाद ८० रनों की मैच विनिंग पारी खेली. मुंबई के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आज भी कोई विकेट नहीं मिला. उन्होंने ४ ओवर में ४१ रन दिए. पंजाब की यह चौथी जीत है, वहीं मुंबई की चौथी हार है.

मुंबई इंडियंस ने २० ओवर में ६ विकेट पर १९५ रनों का स्कोर खड़ा किया है. MI के लिए क्विंटन डिकॉक ने ६० गेंद में नाबाद ११२ रनों की पारी खेली. उन्होंने ८ चौके और ७ छक्के जड़े. नमनधीर ने ३१ गेंद में ५० रन बनाए. उनके बल्ले से ३ चौके और ३ छक्के निकले. इन दोनों के अलावा किसी का भी बल्ला नहीं चला. रियान रिकल्टन आठ गेंद में दो रन, सूर्यकुमार यादव ००, हार्दिक पांड्या १२ गेंद में १४ रन और शरफेन रदरफोर्ड पांच गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए. पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिह ने ४ ओवर में २२ रन देकर तीन विकेट चटकाए.

प्रभसिमरन सिंह साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी अर्धशतक

१३ ओवर के बाद पंजाब किंग्स ने दो विकेट पर १४६ रन बना लिये थे. प्रभसिमरन सिंह ने १० चौके और एक छक्का लगाकर ३२ गेंद में ६६ रन बनाए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीन चौके और दो छक्के के मदतसे २६ गेंद में ४२ रन बनाए थे.

उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक जड़ दिया है. १५ ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर दो विकेट पर १७२ रन है. प्रभसिमरन सिंह ३८ गेंद में ७९ रन पर हैं. वह ११ चौके और दो छक्के लगा चुके थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ३२ गेंद में ५४ रन पर हैं. वह पांच चौके और दो छक्के लगा थे. वही १६ वें ओवर में १८४ के स्कोर पर पंजाब किंग्स का तीसरा विकेट गिरा. अब पंजाब को जीत के लिए ३० गेंद में २४ रन बनाने थे.

१७ वें ओवर मे पंजाब किंग्स सिर्फ तीन विकेट खोकर चौथे विकेट के लिए पारी खलते हुए ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने ३९ गेंद में नाबाद ८० रनों की मदत से मुंबई इंडिन्स को हराकर मैच विनिंग पारी खेलकर जीत हासि की.

पॉइंट्स टेबल में पंजाब बादशाह

मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ IPL २०२६ की शुरुआत की थी. मगर उसके बाद मुंबई की टीम लगातार ४ हार झेल चुकी है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स अब तक एकमात्र टीम है, जिसने आईपीएल २०२६ में हार का स्वाद नहीं चखा है. पंजाब ने ५ मैचों में ४ जीत दर्ज की हैं, जबकि उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. पंजाब अब पॉइंट्स टेबल की नई बादशाह बन गई है.

टी-२० वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग

कप्तान पर ही लगे आरोप

कनाडा क्रिकेट इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है. टीम पर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है. बोर्ड के भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं.

आयसीसी की एंटी-करप्शन यूनाइट ने कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ २ बड़ी जांच शुरू कर दी है. CBC की डाक्यूमेंट्री 'Corruption Cricket and Cricket' में ऐसे दावे किए गए हैं, जिससे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. इस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ के एक मैच से जुड़ा हुआ है, ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ था. न्यूजीलैंड बनाम कनाडा मैच के दौरान मैच फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगा है.

न्यूजीलैंड की पारी में ५वां ओवर जांच के घेरे में है, जो कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने किया था. बता दें कि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ शुरू होने से ३ हफ्ते पहले ही बाजवा को कनाडा नेशनल टीम का कप्तान बनाया गया था. इस ओवर में बाजवा ने नो-बॉल और वाइड बॉल डालते हुए कुल १५ रन दिए थे. ये मैच में महत्वपूर्ण साबित हुआ था. अब ये ओवर जांच के घेरे में आ गया है. आईसीसी इसकी जांच कर रही है कि ये खराब गेंदबाजी सही में थी या जानबूझकर कप्तान ने इतने रन लुटाए थे? क्या ये किसी सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है.

लीक ऑडियो से मचा हड़कंप

कनाडा क्रिकेट टीम अपने बुरे दौर से गुजर रही है. खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप के आलावा टेलीफोन रिकॉर्डिंग ने टीम चयन के दौरान हुई धांधली के भी संकेत दिए हैं, जिसका ऑडियो वायरल है. इसमें पूर्व कोच खुर्रम चौहान का कहना है कि कुछ ख़ास खिलाड़ियों को नेशनल टीम में चुनने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि बोर्ड के ही सीनियर मेंबर्स थे.

पूर्व कोच पुबुदु दस्सानायके ने भी दावा किया है कि २०२४ वर्ल्ड कप के समय उन्होंने भी टीम चयन में अन्य अधिकारियों के दखलअंदाजी का उन्होंने विरोध किया था. इसके बाद उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी गई थी.

कनाडा क्रिकेट की छवि प्रशासनिक स्तर पर भी खराब हुई है. पूर्व CEO सलमान खान पर धोखाधड़ी और चोरी के मामले चल रहे हैं. कनाडा के क्रिकेटर्स की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए मिलने वाली राशि में भी देरी हुई और उन्हें किसी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं रखा.

पंजाब किंग्स की जीत के बाद ७ वें आसमान पर प्रीति जिंटा

नई दिल्ली : आईपीएल २०२६ में पंजाब किंग्स का विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। १६ अप्रैल को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को ७ विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम के सरपंच श्रेयस अय्यर और पूरी टीम की जमकर तारीफ की है।

मैच की पहली पारी में कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार्दिक पांड्या का एक ऐसा अविश्वसनीय कैच लपका कि डगआउट में बैठे रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी दंग रह गए। प्रीति जिंटा ने इस कैच को अब तक का सबसे बेहतरीन कैच बताया। अय्यर ने न केवल अपनी फील्डिग बल्कि बल्लेबाजी से भी मैच पर पकड़ बनाई। उन्होंने ३५ गेंदों में ६६ रनों की कप्तानी पारी खेली। प्रीति ने उन्हें साड्डा सरपंच कहते हुए कोच रिकी पोंटिग के मार्गदर्शन की भी सराहना की।

सलमान खान का स्वैग और प्रीति का सोशल मीडिया पोस्ट

जीत के बाद पंजाब किंग्स के आधिकारिक हैंडल से सलमान खान की स्वर्ण मंदिर की एक पुरानी तस्वीर साझा की गई, जिस पर लिखा था, 'आपा जीत गए!' उधर प्रीति जिंटा ने टीवी पर अपनी टीम की जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीरें शेयर कीं और लिखा कि उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही है।

लाहौर १९४७ से पर्दे पर लौट रही हैं प्रीति

क्रिकेट के मैदान पर टीम की सफलता के साथ-साथ प्रीति अपनी फिल्मी पारी के लिए भी तैयार हैं। वे जल्द ही राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म लाहौर १९४७ में सनी देओल के साथ नजर आएंगी। आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस २०२६ पर रिलीज होने वाली है।

विराट कोहली के एक लाईक ने मचाया बवाल

इस जर्मन ब्लॉगर की तस्वीर की लाईक

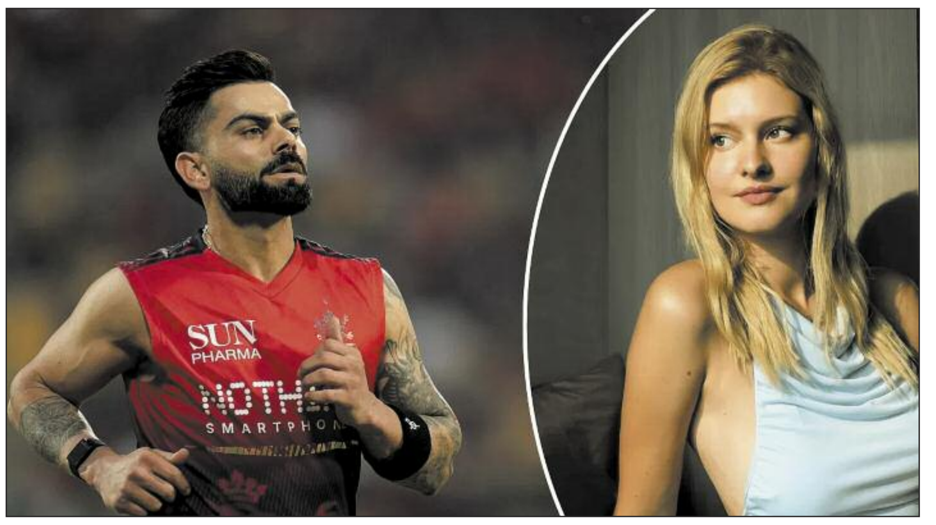

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं और इस बार वजह उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ शतक नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर एक फोटो लाइक करना है। जैसे ही इंटरनेट की पारखी नजरों ने नोटिस किया कि कोहली ने जर्मन-साउथ अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर लिजलाज और फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य की एक पुरानी फोटो लाइक की है, वैसे ही स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। देखते ही देखते लिजलाज भारत में ट्रेंड करने लगीं और फैंस को विराट का पुराना एल्गोरिदम वाला स्पष्टीकरण याद आ गया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में एक मजेदार मीम फेस्ट शुरू हो गया।

कौन हैं समोसा गर्ल लिजलाज?

लिजलाज, जिनका असली नाम जेनिफर है, एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर और सिगर हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की है। वे भारत में अपने समोसा समोसा गाने और बेंगलुरु के ट्रैफिक पर बनाए गए मजेदार वीडियोज के लिए जानी जाती हैं। विराट के एक लाइक ने उन्हें रातों-रात भारतीय फैंस के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

लिजलाज न केवल जर्मन और डच बोलती हैं, बल्कि वे हिंदी और भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों को समझने में भी काफी दिलचस्पी रखती हैं, जो उनके व्लॉग्स में साफ झलकता है।

कोहली के जवाब पर ट्रोल

जैसे ही यह लाइक वायरल हुआ, फैंस ने विराट कोहली को उनके पुराने एल्गोरिदम वाले जवाब पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, इससे पहले जब विराट ने अवनीत कौर की एक फोटो लाइक की थी, तब उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा था कि फीड क्लियर करते समय गलती से एल्गोरिदम ने उस इंटरेक्शन को दर्ज कर लिया था और इसके पीछे उनका कोई इरादा नहीं था। अब लिजलाज वाले मामले में भी फैंस जमकर चुटकी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर विराट के उस पुराने बयान को दोबारा शेयर किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर उड़ा विराट का मजाक

विराट के इस लाइक पर यूजर्स, हर कोई एल्गोरिदम लिखकर मजे ले रहा है। किसी ने मजाक में लिखा कि 'अकाय के हाथ से फोन वापस ले लो', तो किसी ने कमेंट किया कि 'तैयार रहो, एल्गोरिदम पर एक और लंबा पैराग्राफ आने वाला है।' हालांकि, कई फैंस विराट के बचाव में भी आए और इसे महज एक तकनीकी गलती या अनजाने में हुआ लाइक करार दिया। लोगों का कहना है कि विराट जैसा बड़ा सेलिब्रिटी अक्सर ऐसी एल्गोरिदम ग्लिच का शिकार होता रहता है।

आईपीएल में हार्दिक पंड्या का महा-रिकॉर्ड

रसेल और पोलार्ड के खास क्लब में मारी एंट्री ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी

मुंबई : आईपीएल २०२६ में भले ही मुंबई इंडियंस की टीम संघर्ष कर रही हो, लेकिन उनके कप्तान हार्दिक पंड्या ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान हार्दिक ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसे आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं छू सका। आइए इस रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं।

हार्दिक पंड्या अब आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके नाम २५००+ रन, ५०+ विकेट और १५० छक्के दर्ज हैं। हार्दिक से पहले यह कारनामा केवल तीन विदेशी ऑलराउंडर ही कर पाए थे। इनमें शेन वॉट्सन (ऑस्ट्रेलिया), कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज), आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) और अब हार्दिक पंड्या (भारत) है.

हार्दिक न केवल इस क्लब में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, बल्कि वह पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने आईपीएल में यह जादुई आंकड़ा छुआ है।

पूरा किया १५० छक्कों का कोटा

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में हार्दिक ने जैसे ही अपनी पारी का पहला छक्का लगाया, उन्होंने आईपीएल में अपने १५० छक्के पूरे कर लिए। उनके नाम पहले से ही २८०० से ज्यादा रन और ८० विकेट दर्ज हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद हार्दिक के लिए यह रात कड़वी रही, क्योंकि उनकी टीम को पंजाब के हाथों ७ विकेट से हार का सामना करना पड़ा और वह खुद भी गेंद और बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके।

हार्दिक ने साल २०१५ में मुंबई इंडियंस से ही अपना सफर शुरू किया था। बीच में दो साल गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने के बाद वह वापस मुंबई लौटे हैं। उनके नाम अब तक १५६ मैचों में २८३० रन, ८० विकेट दर्ज हैं। वहीं इस दौरान हार्दिक पंड्या ने १५० छक्के जड़े हैं।

'दरार' : बुमराह और हार्दिक के बीच तीखी बहस

मुंबई : मुंबई इंडियंस के खेमे से आ रही खबरें टीम के फैंस की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद अब मैदान के अंदर का तनाव सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एक वायरल वीडियो ने इस चर्चा को हवा दे दी है कि क्या कप्तान हार्दिक पंड्या और स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल इन दोनों खिलाड़ी के बीच मैच के दौरान हॉट-टॉक हुई, जिसके कारण फैंस को टीम में कुछ सही नहीं लग रहा है।

लगातार चौथी हार ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की नींव हिला दी है। पंजाब के खिलाफ १९६ रनों का बचाव करने उतरी मुंबई की गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन हार से ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें बुमराह और हार्दिक के बीच अनबन साफ नजर आ रही है।

मैदान पर बुमराह की नाराजगी और हार्दिक की मनमर्जी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में जसप्रीत बुमराह कप्तान हार्दिक पंड्या के एक फैसले पर बुरी तरह भड़कते हुए दिख रहे हैं। मैच के एक निर्णायक मोड़ पर हार्दिक ने बुमराह की सलाह को दरकिनार कर अपनी रणनीति के हिसाब से फील्डिग सेट की। वीडियो में दिख रहा है कि बुमराह पहले तो कप्तान से बहस करते हैं, लेकिन फिर निराश होकर उनकी बात मान लेते हैं। बुमराह के चेहरे के हाव-भाव साफ बता रहे थे कि वे कप्तानी के फैसलों से खुश नहीं हैं।

मैच के बाद हार्दिक ने खिलाड़ियों को लताड़ा

मैच के बाद हार्दिक पंड्या का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर हैरानी जताते हुए साफ कर दिया कि अब टीम में बड़े बदलावों की जरूरत हो सकती है। हार्दिक ने कहा, 'सच कहूं तो फिलहाल मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हमें वापस जाकर यह देखना होगा कि कमी कहां रह गई है। क्या यह व्यक्तिगत गलती है, टीम की कमी है या प्लानिग फेल हुई? हमें जल्द ही कड़े सवाल पूछने होंगे और जिम्मेदारी लेनी होगी।' हार्दिक ने यह भी संकेत दिया कि अगले मैचों में कुछ सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है या टीम कॉम्बिनेशन में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।

सितारे फेल, गेंदबाजी बेदम

इस मैच में क्विंटन डी कॉक के शानदार शतक और नमन धीर के अर्धशतक के बावजूद बाकी टीम फ्लॉप रही। खुद बुमराह लगातार पांचवें मैच में विकेट के लिए तरसते नजर आए और उन्होंने ४१ रन लुटाए। वहीं, कप्तान हार्दिक ने भी बल्ले से केवल १४ रन बनाए और गेंदबाजी में ३ ओवर में ३९ रन दे डाले। मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला सोमवार, २० अप्रैल को गुजरात टाइटंस से होगा। अगर मुंबई को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो यह मैच उनके लिए हर हाल में जीतना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोमवार तक हार्दिक और बुमराह के बीच के ये मतभेद सुलझ पाएंगे?

अमेरिका में लोकेश सत्यनाथन ने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता

८.२१ मीटर छलांग लगाई खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय

अर्कांसस : भारतीय लॉन्ग जंपर लोकेश सत्यनाथन ने अमेरिका के अर्कांसस में आयोजित NCAA (नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन) डिवीजन-I चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। लोकेश ने ८.२१ मीटर की छलांग लगाकर न केवल अपना पिछला इंडोर नेशनल रिकॉर्ड (८.०१ मीटर) तोड़ा, बल्कि वे यह खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं।

टेक्सास के टार्लेटन स्टेट यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंस की पढ़ाई कर रहे लोकेश अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद को देत हैं। वे फिल्म 'K.G.F: चैप्टर २' के उस दृश्य को याद करते हैं जिसमें नायक अपनी मां से कहता है,यही तुम्हारा सपना था और अब मैं इसे जीतकर दिखाऊंगा।' लोकेश के मुताबिक, अपनी मां के त्याग और उनके शब्दों को याद करने पर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

हादसे में चेहरे पर आई थीं गंभीर चोटें, फिर भी नहीं हारी हिम्मत लोकेश की यह कामयाबी आसान नहीं थी। साल २०२२ में अमेरिका जाने से पहले बेंगलुरु में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। चोटों, दर्द और करियर में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने अपने पिता की ताकत और मां के विश्वास के दम पर मैदान पर वापसी की।

ऑल टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचे इस शानदार जीत के साथ लोकेश सत्यनाथन अब भारत के ऑल टाइम लॉन्ग जंपर्स की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे अब केवल जेस्विन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर जैसे स्थापित नाम ही हैं।

स्वत्वाधिकार लोकमिरर पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड हेतु, प्रकाशक, **मुद्रक एवं संपादक : विशाल दुबे** द्वारा अरुणोदय प्रेस, कॉटन मार्केट, नागपूर - 440018 से मद्रित कर, लोकमिरर पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड C/o. कौशल्याबाई वानखेडे, प्लॉट नं. 177, A/G, योगी अरविन्द नगर, कामठी रोड, नागपूर - 440026 से प्रकाशित। **संपादक : विशाल दुबे**, संपर्क - 09545924968, *पी आर बी कानून के तहत सम्पूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार। RNI Reg. No.-MHHIN/2017/74134